राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में प्रेसनोट,नोटिस,वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उत्तरांचल,उत्तराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रकाशित

सुरत–गुजरात,संस्करण शनिवार 27 मई 2023 वर्ष–6,अंक–122 पृष्ठ–08 मूल्य–01रूपये

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

केजरीवाल ने राहुल गांधी से मुलाकात के लिए मांगा समय, कांग्रेस के लिए क्यों 'धर्म संकट'

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा है। अब कांग्रेस पर नजरें टिकी हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ इन दिनों विपक्षी दलों से समर्थन जुटा रहे केजरीवाल ने तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बाद कांग्रेस से बात करने की इच्छा जाहिर की है। केजरीवाल को समर्थन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी में कई नेता खुलकर बोल रहे हैं और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी आलाकमान का फैसला क्या होता है।

केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह ट्वीट करके बताया कि उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के लिए समय की मांग की है। आप संयोजक ने लिखा, केंद्र सरकार की ओर लाए गए असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक अध्यादेश के

केजरीवाल को समर्थन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी में कई नेता खुलकर बोल रहे हैं और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी आलाकमान का फैसला क्या होता है।

खिलाफ संसद में समर्थन, संघीय ढांचा पर प्रहार और मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी जी से आज सुबह समय मांगा है। शराब घोटाले और बंगले पर करोड़ों खर्च जैसे आरोपों से घिरे अरविंद केजरीवाल को इन दिनों केंद्र सरकार से अधिकारों की जंग का सामना भी करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से मिला अधिकार अध्यादेश से छिन जाने के बाद केजरीवाल इसका रास्ता राज्यसभा में रोकना चाहते हैं।

क्यों कांग्रेस के लिए है धर्म संकट की घड़ी

कांग्रेस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन करके राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल ने देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के ऐक्शन और अधिकारों की लड़ाई में आप कांग्रेस से समर्थन की उम्मीद कर रही है। आप को समर्थन के मुद्दे पर कांग्रेस में मतभेद है। दिल्ली, पंजाब, गुजरात से लेकर गोवा तक के नेता एक ऐसी पार्टी को समर्थन देने का विरोध कर रहे हैं, जिसने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली और पंजाब में आप ने कांग्रेस से सत्ता छीन ली तो गुजरात और गोवा में भी उसके वोटशेयर से हिस्सा बांट लिया है। विरोध करने वालों में वरिष्ठ नेता अजय माकन प्रमुख हैं, जो यह भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने के लिए प्रस्ताव पास किया, ऐसे नेता को समर्थन कैसे दिया जा सकता है?

साझा घर पर बहू का हक नहीं, ससुराल वालों को बाहर नहीं निकाला जा सकता

नई दिल्ली। ससुराल वालों संग संपत्ति विवाद में बहू को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कानून के तहत बहू के पास 'साझा घर' में रहने का अपरिहार्य अधिकार नहीं है और ससुराल वालों को इससे बाहर नहीं किया जा सकता है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने हाल ही पारित अपने फैसले में कहा है कि 'साझा घर' की अवधारणा स्पष्ट रूप से यह कहती है कि एक साझा घर में बहू का अधिकार एक अपरिहार्य अधिकार नहीं है और ससुराल वालों के इससे बाहर नहीं निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि बहू अपने वैवाहिक घर या साझा घर में रहने के अधिकार का दावा करते हुए यह दलील नहीं दे सकती है कि साझा घर में ससुराल वाले उसके साथ नहीं रह सकते। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा है कि 'अगर ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो दर्शाती हैं कि वे एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो बहू के लिए वैकल्पिक आवास भी तलाशे जा सकते हैं।' हाईकोर्ट ने संभागीय आयुक्त के 31 मार्च को आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह टिप्पणी की है। बहू ने संभागीय आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ याचिका दाखिल की है। महिला के ससुरालवालों की ओर से 'माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देखरेख व कल्याण अधिनियम' के तहत साउथ एक्टेंशन में मकान से बहू को घर से बेदखल करने की मांग की थी। जिलाधिकारी ने इस मामले में बहू को घर खाली करने का निर्देश दिया था। हालांकि संभागीय आयुक्त ने बहू को घर खाली करने के जिलाधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया और बहू को घर में रहने की अनुमति दे दी। हालांकि, संभागीय आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि ससुरालवाले जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं, वो भी उसी मकान में रहेंगे। इसी आदेश को महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस को मिल सकता है नया अध्यक्ष, कन्हैया कुमार समेत 4 चार नाम रेस में शामिल

नई दिल्ली। कांग्रेस की दिल्ली इकाई को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नया अध्यक्ष मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, इस पद के लिए संदीप दीक्षित, देवेंद्र यादव, अरविंदर सिंह लवली और कन्हैया कुमार के नामों की चर्चा चल रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के मौजूदा अध्यक्ष अनिल चौधरी का तीन साल का कार्यकाल इस साल मार्च में समाप्त हो चुका है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि दिसंबर में होने वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव के बाद डीपीसीसी को नया अध्यक्ष मिलना था, लेकिन प्रक्रिया में देरी हुई। राजधानी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने एमसीडी चुनाव जीता था।

सूत्रों ने दावा किया कि किया कि डीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष लवली और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं। जबकि देवेंद्र यादव उत्तराखंड के लिए कांग्रेस के प्रभारी हैं, जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, भाकपा

छोड़ने के बाद 2021 में पार्टी में शामिल हुए थे।

कांग्रेस के एक सूत्र ने बताया, चार नाम हैं जिन पर अध्यक्ष पद (डीपीसीसी) के लिए विचार किया जा सकता है। इसमें संदीप दीक्षित, देवेंद्र यादव, अरविंदर सिंह लवली और कन्हैया कुमार के नाम शामिल हैं। सूत्र ने बताया, एमसीडी चुनाव के बाद डीपीसीसी का नया अध्यक्ष चुना जाना था, लेकिन प्रक्रिया में देरी के कारण ऐसा नहीं हो सका।

11 फर्मों को दवा उत्पादन बंद करने का आदेश

सोलन। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (डीसीए) ने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़, सिरमौर और कांगड़ा जिलों के औद्योगिक केंद्र में स्थित 11 फार्मास्युटिकल फर्मों से दवा उत्पादन बंद करने को कहा है। यह आदेश हाल ही में किए गए जोखिम-आधारित निरीक्षणों के दौरान इसके कामकाज में महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बाद दिया गया है। इस बारे में स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर नवनीत मारवाहा ने कहा, पिछले दो महीनों में राज्य डीसीए और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन द्वारा संयुक्त रूप से किए गए निरीक्षण के दूसरे चरण में 29 फर्मों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जीएमपी) की अनुसूची एम से संबंधित बड़ी खामियों के

चलते उत्पादन बंद करने के लिए कहा गया है, शेष 18 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही फर्मों से इन खामियों को दूर करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि अधिकारियों ने उन टिप्पणियों को साझा नहीं किया जिनके कारण इस तरह की कार्रवाई की गयी, लेकिन जानकारी मिली है कि इन फर्मों में खराब लैब उपकरण जैसी चीजें मिलीं। बताया गया कि मशीनरी के सत्यापन जैसे प्रमुख मुद्दों की भी जांच की जा रही है क्योंकि यह देखा गया है कि कई कंपनियां अपनी मशीनरी का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने में विफल रहती हैं, जो दवाओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। मारवाहा ने हालांकि कहा कि बार-बार घटिया दवाओं के मासिक अलर्ट की सूची में आने वाली फर्मों पर नजर रखी जा रही है।

सुधार के लिए मिलता है एक मौका

बताया गया कि खामी संबंधी टिप्पणी के बाद फर्म को कुछ समय दिया जाता है। यदि अपेक्षित सुधार करने का दावा किया जाता है तो वहां फिर जांच की जाती है। इस प्रक्रिया में 20 दिन से दो माह तक का समय लगता है।

वंदे भारत एक्सप्रेस के दिखेंगे 2 नए अवतार, फरवरी तक चलाने की तैयारी में रेलवे

नई दिल्ली। वंदे भारत एक्सप्रेस धीरे-धीरे भारतीय रेलवे की पहचान बनती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त तक देश के 75 रूटों पर इसे चलाने का लक्ष्य दिया है। अभी तक 17 ऐसी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। इसके अलावा अगले साल तक देश के इस स्वदेशी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन के दो और संस्करण लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। दोनों तरह की ट्रेनें फरवरी 2024 तक पटरी पर दौर सकती है। वर्तमान में देश में वंदे भारत एक्सप्रेस का केवल एक संस्करण पटरी पर दौर रहा है। इस ट्रेन को अधिकतम 8 घंटे की दूरी तय करने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें सिर्फ दो तरह के कोच होते हैं। चेयर कर और एग्जिक्यूटिव क्लास। रेलवे ने इस वित्त वर्ष में दो नए संस्करण लॉन्च करने की योजना बनाई है। पहल है वंदे मेट्रो और दूसरा वंदे स्लीपर्स। वंदे भारत एक्सप्रेस ने भारतीय रेलवे के यात्रियों के अनुभव को बेहतर है। इन ट्रेनों को राजधानी, शताब्दी और लोकल ट्रेनों की जगह लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में ये तीनों संस्करण चेन्नई स्थित इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं। वंदे भारत के विभिन्न संस्करणों को तीन अलग-अलग मार्गों पर चलाया जाएगा। वंदे

भारत चेयर कार को 100 से लेकर 550 किलो मीटर की दूरी के बीच चलाया जा रहा है। वहीं, वंदे मेट्रो को 100 किलोमीटर से कम की दूरी वाले रूट पर चलाया जाएगा। वहीं, वंदे स्लीपर ट्रेन को 550 किलोमीटर से अधिक दूरू की यात्रा के लिए चलाया जाएगा। रेलवे ने इन दोनों मॉडलों को फरवरी या मार्च 24 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है।

2024 में फिर प्रधानमंत्री बनें नरेंद्र मोदी, सेंगोल भेंट करने वाले पुजारी ने दिया आशीर्वाद

नई दिल्ली। नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल भेंट करने वाले मदुरै अधीनम के मुख्य पुजारी श्री हरिहर देसिका स्वामीगल ने कहा कि प्रधानमंत्री को 2024 में सत्ता में वापस आना चाहिए और देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यह वही राजदंड है, जिसे 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से भारत में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर प्राप्त किया था। उद्घाटन के दौरान इसे मदुरै अधीनम के 293वें प्रधान पुजारी द्वारा प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, पीएम मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्हें दुनिया के कई देशों की सराहना मिली है। वह लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। 2024 में फिर से उन्हें पीएम बनना है। उन्हें लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए। हम सभी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि विश्व के नेता हमारे पीएम मोदी की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं पीएम मोदी

से मिलूंगा और नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर उन्हें सेंगोल भेंट करूंगा।

वहीं, ऐतिहासिक राजदंड बनाने वाले वुम्मिदी बंगारू ज्वैलर्स के चेयरमैन वुम्मिदी सुधाकर ने बताया, हम सेंगोल के निर्माता हैं। इसे बनाने में हमें एक महीने का समय लगा है। यह चांदी का है। इसपर सोना चढ़ाया हुआ है। यह जब बना तब मैं 14 साल का था। हम पीएम मोदी के आभारी हैं।

आपको बता दें कि सेंगोल को पीएम द्वारा लोकसभा में स्पीकर के पोडियम के पास स्थापित किया जाएगा। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। समारोह दोपहर 12 बजे शुरू होगा। दोपहर 1:30 बजे तक इसके समाप्त होने की उम्मीद है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट, काम भी हुआ शुरू,

ग्रेटर नोएडा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। इसके बनने से जेवर एयरपोर्ट और आईजीआई एयरपोर्ट आपस में जुड़ जाएगा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा के बल्लभगढ़ से गुजर रहा है। बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट की दूरी करीब 31 किलोमीटर है। इसका नया लिंक रोड बनाकर जेवर एयरपोर्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। इसमें से 8.5 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। बाकी हिस्सा हरियाणा के अधीन है। इस 8.5 किलोमीटर के लिए 66.73 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई है। यह जमीन छह गांव में आती है। इसको खरीदने में 260 करोड़ खर्च हुए हैं।

डीएम ने करवाई शुरुआत– गुरुवार को डीएम मनीष वर्मा ने लिंक रोड का ग्राम दयानतपुर में शुभारंभ किया। डीएम ने कहा कि यह लिंक रोड जेवर क्षेत्र में बनाए जा रहे एयरपोर्ट, बल्लभगढ़ नेशनल हाईवे, आईजीआई तथा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को जोड़ेगा।

ये लाभ होंगे

1. इस लिंक रोड से जेवर से दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचने में पहले से समय कम लगेगा।

2. हरियाणा के इलाकों में पहुंचने के लिए एक और बेहतर विकल्प लोगों को मिलेगा।

3. नया लिंक रोड जेवर क्षेत्र के विकास के मार्ग को और प्रशस्त करेगा।

4. यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित हो रहे औद्योगिक सेक्टर को फायदा मिलेगा।

यह काम भी कराएगा एनएचएआई

एयरपोर्ट बाउंड्री तक लिंक रोड

इसमें से 8.5 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। बाकी हिस्सा हरियाणा के अधीन है। इस 8.5 किलोमीटर के लिए 66.73 हेक्टेयर जमीन खरीदी गई है। यह जमीन छह गांव में आती है। इसको खरीदने में 260 करोड़ खर्च हुए हैं।

बनेगी– इंटरचेंज से एयरपोर्ट की बाउंड्री तक जोड़ने के लिए 700 मीटर नई सड़क बनानी होगी। यह लिंक रोड एलिवेटेड होगी। इसके लिए 4.42 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। इस पर 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सड़क के निर्माण पर करीब 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इंटरचेंज बनाया जाएगा–दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बन रहा लिंक रोड यमुना एक्सप्रेसवे के करीब 30वें किलोमीटर पर मिलेगा। यहां पर इंटरचेंज बनाया जाएगा। इस इंटरचेंज को बनाने में 19 हेक्टेयर जमीन लगेगी। जमीन खरीदने में करीब 76 करोड़ रुपये लगेंगे, जबकि निर्माण में करीब 150 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

एनएचएआई ने पिलर लगाए

नई लिंक रोड के लिए दयानतपुर, करौली बांगर, वल्लभनगर, अमरपुर पलाका आदि की जमीन ली गई है। जिला प्रशासन ने जमीन पर कब्जा लेकर एनएचएआई को सौंप दिया है। एनएचएआई ने अपनी जमीन पर पिलर लगा दिए हैं। गुरुवार को लिंक रोड का निर्माण शुरू कर दिया गया है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

उद्घाटन और शिकायत

भारत वस्तुत- विविध मत-अभिमत से समृद्ध देश है। इस विशाल देश में कदम-कदम पर विरोध और विरोधाभासों का सामने आना सहज व स्वाभाविक है। भारत के नए संसद भवन परिसर का उद्घाटन एक खुशी का अवसर है, लेकिन इस खुशी के अवसर पर एक शिकायत राजनीतिक गलियारों से होती हुई सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गई है। एक अधिवक्ता ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के अवसर पर आमंत्रित न किए जाने की शिकायत सर्वोच्च न्यायालय में कर दी है, इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट भले पहली सुनवाई में ही टाल दे या खारिज कर दे, लेकिन यह अपने आप में मानीखेज है कि ऐसी शिकायत भी कोई कर सकता है। क्या ऐसा कोई कानून है, जो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में सांविधानिक पदों पर बैठी विभूतियों को आमंत्रित करने संबंधी कोई दिशा-निर्देश देता है? क्या केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति को उद्घाटन कार्यक्रम में न बुलाकर कोई त्रुटि की है? अगर यह प्रक्रियागत त्रुटि है, तो क्या कानून के तहत भी कमी मानी जा सकती है? इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय को जल्दी करना होगा। यदि इस शिकायत को अदालत में ज्यादा समय तक सुना गया, तो इसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा और इससे सिर्फ सियासत को बल मिलेगा। 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित न करना विधायिका या कार्यपालिका द्वारा किया गया फैसला है और इसकी विवेचना अवश्य होनी चाहिए। यह राजनीति का विषय ही नहीं है, व्यावहारिकता से जुड़ा विषय है। ऐसे विषयों पर किसी भी व्यवस्था में बहस लगातार होती रहती है और समय के साथ उसमें सुधार भी होते रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में यह शिकायत भी शामिल है कि राष्ट्रपति को ऐसे कार्यक्रम से बाहर रखना अपमान के बराबर है और गुहार लगाई गई है कि राष्ट्रपति को आमंत्रित करने के निर्देश केंद्र सरकार को दिए जाएं। न्यायपालिका अगर ऐसे फैसले करने लगेगी, तो जाहिर है, कार्यपालिका को बहुत समस्या होगी। क्या ऐसे में बेहतर यह नहीं है कि विधायिका ऐसे आयोजनों के बारे में एक प्रोटोकॉल बनाए कि कहां किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है? सार्वजनिक आयोजनों से जुड़े फैसलों को चार-पांच लोगों के विवेक पर छोड़ना क्या सही है? कम से कम राष्ट्रपति और राज्यपाल के मामले में आमंत्रण या कार्यक्रम संबंधी दिशा-निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। अगर ये अभी तक नहीं बनाए गए हैं, तो बना लेने चाहिए, क्योंकि राजनीति की जो दशा-दिशा है, उसमें आने वाले समय में इस तरह के विवाद बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे दिशा-निर्देश मजबूरी में अगर न्यायपालिका बनाने लगे, तो फिर विधायिका के स्वाभिमान को ही चोट लगेगी। गौर करने की बात है कि दायर याचिका में संविधान के अनुच्छेद 79 का हवाला दिया गया है, जो बताता है कि एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदनों का समावेश होगा। क्या राष्ट्रपति को उद्घाटन कार्यक्रम में न बुलाना अनुच्छेद 79 का उल्लंघन है? इस विवाद की पृष्ठभूमि यह भी है कि 11 राज्य सरकारों को नियंत्रित करने वाली 19 पार्टियों के एक संयुक्त बयान में नई संसद के उद्घाटन संबंधी फैसले को लोकतंत्र पर हमला बता दिया गया। क्या इसके पहले कभी राष्ट्रपति के पद को नजरअंदाज नहीं किया गया है? यहां अफसोसनाक उदाहरण गिनाने की जरूरत नहीं है, पर समय आ गया है, जब ऐसे गंभीर सवालों को राजनीति से ऊपर उठकर हल किया जाए।

आज का राशीफल

मेष शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। किसी रिश्तेदार के आगमन से मन प्रसन्न होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक कष्टों का सामना करना पड़ेगा।

वृषभ पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। खान-पान में संतुलन बना कर रखें। मकान, सम्पत्ति व वाहन की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा।

मिथुन दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। आय के नये स्त्रोत बनेंगे। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी अपेक्षित है।

कर्क पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। स्थानान्तरण व परिवर्तन की दिशा में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। धन लाभ होगा।

सिंह रोजी रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

कन्या पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा।

तुला आर्थिक योजना सफल होगी। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी रिश्तेदार से तनाव मिल सकता है। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

वृश्चिक पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। रोजी रोजगार की दिशा में प्रगति होगी। अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग रहेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे।

धनु जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। फिजूलखर्ची से बचें अन्यथा कर्ज की स्थिति आ सकती है। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। धन हानि की संभावना है।

मकर दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

कुम्भ गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। खान पान में संयम रखें। स्वास्थ्य शिथिल रहेगा। आमोद प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी।

मीन पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। नेत्र विकार की संभावना है। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

मूल्यों-आदर्शों के प्रतीक बनें जनतंत्र के मंदिर

विश्वनाथ सचदेव

निश्चित रूप से यदि नये संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होता तो यह अधिक गरिमामय होता। लेकिन आज जो राजनीति हम देख रहे हैं उसमें गरिमा अथवा औचित्य के लिए स्थान ही कहां बचा है। होना तो यह चाहिए था स्वयं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इस कार्य के लिए आमंत्रित करते। पर जो होना चाहिए, वह होता कहां है हमारी राजनीति में? कौन जानता है कि हमारे पुराने संसद-भवन का उद्घाटन किसने किया था? और आवश्यकता भी क्या है ऐसे औपचारिक अवसरों को याद करने या याद रखने की?

जब हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में अपने नेतृत्व को रेखांकित करने- कराने में लगे हुए थे तो देश में उन्हें लेकर एक बेमतलब का विवाद शुरू हो गया था। मुद्दा संसद के नये भवन के उद्घाटन का है। बहुचर्चित नया संसद परिसर लगभग बनकर तैयार है और अब इसे देश को लोकार्पित किया जाना है। लोकसभा के स्पीकर ने उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रित किया है। विपक्ष का कहना है कि यह कार्य देश के प्रथम नागरिक अर्थात ् राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। यह मांग भी ग़लत नहीं कही जा सकती, आखिर देश के सर्वोच्च संस्थान के उद्घाटन का मामला है। उधर प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन कराने के पक्षधरों का कहना है कि प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च निर्वाचित नेता होता है और यह नया संसद परिसर तो प्रधानमंत्री मोदी की प्रिय परियोजना है। कोरोना-काल में जब देश के सारे निर्माण-कार्य ठप पड़ गये थे, इस परिसर का काम नहीं रोका गया था, और निर्माण कार्य के दौरान प्रधानमंत्री लगातार इसकी निगरानी कर रहे थे। क्या बुरा है यदि उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों हो? सवाल वाजिब है। पहले भी तो पूर्व प्रधानमंत्री संसद से जुड़े संस्थानों के उद्घाटन करते रहे हैं। 'दूरदर्शन' ने तो राजीव गांधी के हाथों होने वाले ऐसे उद्घाटन की फिल्म भी देश के सामने रख दी है। सच पूछा जाये तो यह विवाद का विषय है ही नहीं। होना ही नहीं चाहिए। पर जिस तरह की राजनीति आज देश में हो रही है, अनावश्यक मुद्दे हथियार बनाये जा रहे हैं। निश्चित रूप से यदि नये संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होता तो यह अधिक गरिमामय होता। लेकिन आज जो राजनीति हम देख रहे हैं उसमें गरिमा अथवा औचित्य के लिए स्थान ही कहां बचा है। होना तो यह चाहिए था स्वयं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इस कार्य के लिए आमंत्रित करते। पर जो होना चाहिए, वह होता कहां है हमारी राजनीति में? कौन जानता है कि हमारे पुराने संसद-भवन का उद्घाटन किसने किया था? और आवश्यकता भी क्या है ऐसे औपचारिक अवसरों को याद करने या याद रखने की? महत्वपूर्ण संसद-भवन नहीं संसद-भवन के भीतर होने वाली कार्यवाही है। कौन नहीं जानता कि पिछले कुछ सालों में हमारी संसदीय कार्यवाही में लगातार गिरावट आयी है? संसद के भीतर होने वाली बहस का स्तर तो गिरा ही है, अक्सर हमने देखा है कि संसद का बहुमूल्य समय बेबात के विवादों की बलि चढ़ता रहा है। संसद के हर सत्र के बाद इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं जो यह बताते हैं कि संसद का कितना समय शोर-शराबे और बहिर्गमन और काम में व्यवधान डालने में बर्बाद होता है। हमारे नेताओं ने तो इस बात की भी वकालत की है कि संसद के काम में रुकावट डालना भी संसदीय कार्य-प्रणाली का हिस्सा है! यहां यह याद करना महत्वपूर्ण होगा कि यह तर्क तत्कालीन विपक्ष के नेताओं ने दिया था। अर्थात ् जो भी विपक्ष में होता है, इस तरह के तर्कों का सहारा लेता है। यह एक संयोग ही है कि जब नये संसद-भवन के उद्घाटन को लेकर देश में विवाद चल रहा है तो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केरल विधानसभा भवन के रजत-जयंती समारोह में संसद और विधानसभा सदनों में काम-काज में रुकावट डालने को राजनीतिक रणनीति का हथियार बनाने की प्रवृत्ति के खिलाफ देश को आगाह कर रहे थे। उन्होंने सदनों के अध्यक्षों से आगाह किया कि वे इस बारे में राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम करें कि जनतंत्र के मंदिरों का उपयोग उपयोगी बहस और सार्थक कामकाज के लिए ही हो। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने इस बात को रेखांकित किया कि यदि संसद में होने वाला कार्य दूसरों को अनुकरणीय नहीं लगता तो इसका मतलब यह है कि हमारे सोच में कहीं कोई खामी है। उन्होंने विधानसभा परिसर के पुनर्विकास के लिए आधारशिला भी रखी। आधारशिला वाली बात का रिश्ता कहीं न कहीं इस तथ्य के साथ भी है कि पुनर्विकास का मतलब संसदीय परंपराओं को बनाये रखने से भी होता है। आज जब हम नये संसद-परिसर के उद्घाटन समारोह के साक्षी बन रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखा जाना ज़रूरी है कि जनतंत्र का हमारा मंदिर जनतांत्रिक मूल्यों-आदर्शों के अनुरूप कार्य का उदाहरण बने। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि उद्घाटन किसके हाथों हो, महत्वपूर्ण यह है कि उद्घाटन के बाद वहां काम कैसा हो रहा है। वैसे इस संदर्भ में विपक्ष यह बात भी कह रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री को उद्घाटन-समारोहों से कुछ ज़्यादा ही मोह है। छोटे-छोटी परियोजनाओं का उद्घाटन वे स्वयं करना पसंद करते हैं। किसी राजमार्ग का उद्घाटन करना कतई ग़लत नहीं है, पर राजमार्ग के छोटे से हिस्से का उद्घाटन प्रधानमंत्री करें, यह बात कुछ उपयुक्त नहीं लगती। इसी तरह वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत प्रधानमंत्री करें यह तो समझ आता है, हर नये रूट पर वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री ही हरी झंडी दिखायें यह कुछ अजीब तो लगता ही है। कुछ काम करने का श्रेय तो रेल मंत्री या परिवहन मंत्री को भी मिलना चाहिए। विपक्ष इस प्रवृत्ति को आत्म-प्रचार और आत्म-श्लाघा से जोड़ रहा है। बहरहाल, उद्घाटन वाला यह विवाद न उठता तो अच्छा था। पता नहीं प्रधानमंत्री की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। अभी तक तो भाजपा के अन्य नेतागण ही इस बारे में बोल रहे हैं। पर यदि किसी रूप में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से कार्यक्रम की भव्यता बढ़ जायेगी। इसे राजनीतिक नफे-नुकसान का माध्यम बनाना किसी भी पक्ष के लिए उचित नहीं है। प्रधानमंत्री स्वयं पहल करके इसकी भव्यता को बढ़ा सकते हैं। सही रास्ते पर चलने वाला नेता निःसंदेह बड़ा होता है, पर सही रास्तों का पता लगाने, उन्हें काटों-कंकड़ों से मुक्त बनाकर उन पर देश और समाज को चलाने वाला नेता कहीं अधिक बड़ा होता है। हमारे नेतृत्व को चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों न हो, इस परीक्षा में लगातार सफल होना है। सवाल सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष का नहीं है, राजनीतिक संस्कृति के परिष्कार का है। इस कार्य में हमारा नेतृत्व अक्सर विफल होता ही दिखा है। जुमलेबाजी वाली राजनीति से बचना-बचाना ज़रूरी है। चुनाव-दर-चुनाव हम इस प्रवृत्ति के खतरनाक परिणाम देखते आ रहे हैं। संसद भवन में जुमलेबाजी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संसद से जुड़े हर कार्य में, उद्घाटन समारोह में भी, एक गरिमा दिखनी चाहिए। इस बात को हमारा नेतृत्व कब समझेगा?

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

कांग्रेसी अगुआई को लेकर क्षेत्रीय दलों की चिंताएं

उमेश चतुर्वेदी

कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद गैर भाजपा दलों का खुश होना स्वाभाविक है। यह बात और है कि बंगलुरू में गत 20 मई को हुए सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में यह प्रसन्नता कम ही दिखी। वहां जुटे विपक्षी नेताओं की मौजूदगी सिर्फ सांकेतिक ही नजर आई। विपक्षी राजनीति का कोई ठोस संकेत नहीं मिला। इसके बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी शिद्दत से विपक्षी एकता की कमान थाम लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी मुलाकात को इसी नजरिये से देखा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन मुलाकातों के बावजूद कांग्रेस विपक्षी एकता के लिए अपने नेतृत्व को कुर्बान करने को तैयार होगी? कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस क्या विपक्षी गोलबंदी में उसी तरह पृष्ठभूमि में रहने को तैयार होगी, जैसे कर्नाटक चुनाव के पहले तक दिख रही थी? दरअसल, जिस तरह नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी मुहिम की अगुआई करने की कोशिश में जुटे हैं, उससे लगता है कि उन्होंने मोदी को सत्ता से बाहर करने का संकल्प ले लिया है। दो महीने पहले जनता दल यू की कार्यकारिणी का गठन किया था, लेकिन तब पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार केसी त्यागी को कोई जगह नहीं मिली थी। ऐसा नीतीश की मर्जी के बिना तो नहीं ही हुआ होगा। लेकिन मोदी विरोधी अभियान छेड़ने के बाद उन्हीं केसी त्यागी की उपयोगिता नीतीश कुमार को समझ आने लगी है। इसकी वजह है, केसी त्यागी का तमाम पार्टियों के नेताओं से सुमधुर रिश्ता रहना। नीतीश को उम्मीद है कि विपक्षी लामबंदी में केसी त्यागी के राजनीतिक रिश्ते उनके लिए कारगर हो सकते हैं। नीतीश की कोशिशों से 1987 के विपक्षी अभियानों की याद आना स्वाभाविक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोफोर्स दलाली के आरोपों से जूझ रहे थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुआई में अरुण नेहरू, रामधन, आरिफ मोहम्मद खान और सतपाल मलिक ने कांग्रेस से अलग राह अपना ली थी। तब नीतीश कुमार, शरद यादव के राजनीतिक शागिर्द माने जाते थे, उन दिनों शरद के राजनीतिक बॉस देवीलाल का हरियाणा की सत्ता पर कब्जा था। तब उन्होंने राजीव विरोधी परिवर्तन रथ चला रखा था। आंध्र प्रदेश के नेता नंदमुरि तारक रामाराव ने भी तेलुगू देशम पार्टी के बैनर तले यात्रा निकाल रखी थी। साल 1987 में समूचे विपक्ष को एक होने का मौका इलाहाबाद उपचुनाव से मिला था, जिसमें राजीव के लेफ्टिनेंट रहे वीपी सिंह उतरे थे और कांग्रेस के उम्मीदवार और उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन कांग्रेसी मंत्री सुनील शास्त्री को हरा दिया था। नीतीश भी इन दिनों कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन वीपी सिंह जैसी एकता होती नजर नहीं आ रही है। बीस मई को बंगलुरू में हुए सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी को बुलावा नहीं मिला। जिस ममता बनर्जी को मिला, उन्होंने खुद आने की बजाय अपनी एक सांसद को भेज दिया। विपक्षी राजनीति के कद्दावर चेहरे शरद पवार भी बंगलुरू में नजर नहीं आए। के. चंद्रशेखर राव को भी निमंत्रण नहीं था। आंध्र के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को कांग्रेस से बुलावा मिलना ही नहीं था। विपक्षी राजनीति के एक और अहम चेहरे नवीन पटनायक भी वहां नहीं पहुंचे। जाहिर है कि विपक्षी एकता बनने के पहले ही बिखर गयी। साल 2018 में हुए एचडी कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में भी विपक्षी दिग्गज जुटे थे, लेकिन अगले ही साल हुए लोकसभा चुनावों में विपक्ष की मौजूदगी खास नहीं रही। इस बार तो समूचा विपक्ष रहा भी नहीं, ऐसे में विपक्षी एकता की कैसे उम्मीद की जा सकती है? विपक्षी राजनीति के दिग्गजों में कांग्रेस के साथ दिखने में हिचक की वजह है मुस्लिम वोट बैंक। कर्नाटक में जिस तरह कांग्रेस का मुस्लिम वोटरों ने एकमुश्त समर्थन किया है, उससे कई भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दल सशंकित हैं। विशेषकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में जहां करीब 18 प्रतिशत मुस्लिम वोटर हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में करीब 30 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं। भारतीय राजनीति में अतीत में इस वोट बैंक पर सिर्फ कांग्रेस का ही असर होता था। लेकिन राम मंदिर आंदोलन और सामाजिक न्याय की राजनीति के दौर में मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से दरकता हुआ हर प्रदेश में उन दलों के साथ जुड़ता गया, जिनसे उन्हें सांप्रदायिकता विरोध के नाम पर भाजपा को हराने की उम्मीद थी। मसलन, उत्तर प्रदेश में साल 2012 तक समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस व दिल्ली में आम आदमी पार्टी। अभी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कम से कम विधानसभा चुनावों तक खतरा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनावों में यह वोट बैंक आप की बजाय कांग्रेस की ओर कर्नाटक की तरह लौट सकता है। इसलिए क्षेत्रीय दलों की चिंता स्वाभाविक है। इसीलिए वे कांग्रेस की अगुआई में नया विपक्षी गोलबंदी के लिए उतावले नजर नहीं आ रहे हैं। मुस्लिम जनाधार खिसकने का खतरा महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ भी हो सकता है। रही बात नीतीश कुमार की, तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वैसे भी नीतीश की उम्र हो गई है, इसलिए उन्हें भी लगता है कि अपनी जिंदगी के तकरीबन आखिरी चुनाव में कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। कर्नाटक से बदले माहौल में कांग्रेस की अपनी सोच, नीतीश की कोशिश और विपक्षी आशंका के चलते विपक्षी एकता व मोदी विरोधी लामबंदी में अभी कई कलाबाजियां दिख सकती हैं।

राजतंत्र से लोकतंत्र, में राजदंड का सफर?

लेखक- सनत जैन

भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह आजादी के 75 वें साल में होने जा रहा है द्य इस ऐतिहासिक समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। हजारों वर्षों की राजतंत्र की गुलामी के बाद 1947 में मिली आजादी के बाद लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आई। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। संविधान में जनता का, जनता के द्वारा जनता पर शासन को लोकतंत्र के रूप में परिभाषित किया गया। संसद भवन में संविधान को शासन व्यवस्था का प्रतीक मानकर रखा गया। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में एक जो नई बात होने जा रही है। उसमें राजसी परंपरा का राजदंड स्थापित करने को लेकर देश में नई बहस शुरू हो गई है द्य यह कहा जा रहा है,कि आजादी के 75 वर्ष बाद क्या हम एक बार फिर राजतंत्र की ओर लौट रहे हैं। राजतंत्र में राजदंड की व्यवस्था होती थी। नए संसद भवन में राजदंड को स्थापित कर वर्तमान सरकार लोकतंत्र को, राजतंत्र में परिवर्तित करने के लिए राजदंड की स्थापना करने जा रही है? भारत अब लोकतांत्रिक राष्ट्र के स्थान पर हिंदू राष्ट्र बनाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी देते हुए बताया है,कि तमिलनाडु से आए विद्वान धार्मिक क्रियाओं को पूर्ण करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैंगोल (राजदंड) सौंपेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा,कि यह राजदंड 15 अगस्त 1947 की आधी रात को अंग्रेज वाइसराय ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के समय सौंपा था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा था, कि सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सी राजगोपालाचारी ने जो मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उन्होंने नेहरू को राजदंड भेंट करने वाली तमिल राजवंश की परंपरा के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि नए राजा को सत्ता ग्रहण करते समय राजदंड भेंट किया जाता है। जिस तमिल राजा की परंपरा का उन्होंने उल्लेख किया उस राजा का राजदंड राजगुरु थिरवदथुरै मठ के अधीन था। राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया था, कि आपके प्रधानमंत्री बनने पर माउंटबेटन राजदंड, स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में ले सकते हैं। कांग्रेस पार्टी एवं जवाहरलाल नेहरु राजगोपालाचारी के इस मार्गदर्शन से सहमत हो गए थे। इसकी जानकारी उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को दी। राजा गोपालाचारी के निर्देशन में मद्रास के 1 जोहरी को सोने का राजदंड बनाने को कहा गया। राजदंड के ऊपर नंदी की आकृति उकेरी गई। राजदंड को दिल्ली लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष विमान भेजा था। 14 अगस्त 1947 की रात 11:45 बजे मठ के पुजारी ने यह राजदंड माउंटबेटन को सौंपा था। इसके बाद राजदंड में पवित्र जल छिड़का गया, इसे सत्ता परिवर्तन के समय जवाहरलाल नेहरू को सौपा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत किस तरह की शासन व्यवस्था को अपनाए। इसके लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा में सभी पक्षों के विद्वानों को रखा गया। संविधान सभा ने स्वतंत्रता के पश्चात नागरिकों के मौलिक अधिकार और राजतंत्र के स्थान पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को वरीयता दी। 26 जनवरी 1950 को संसद में संविधान को स्थापित किया गया। उसके बाद से संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शासन संचालित हो रहा है। जिसमें जनता ही शासक है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जनता का, जनता के द्वारा, जनता का शासन, की अवधारणा से शासन व्यवस्था चल रही है। भारत में राजाओं द्वारा राज तिलक होने के अवसर पर राजपुरोहित के माध्यम से राजदंड नए राजा को प्रदान किया जाता था। धार्मिक आस्था और परंपरा के अनुसार राजदंड के विशेषाधिकार से शासन व्यवस्था चलाने की परंपरा राजतंत्र में रही है। हिंदू मठ और सन्यासियों के गुरुकुल में दंड के माध्यम से शिष्यों को नियंत्रित किए जाने परंपरा रही है। 1947 में भारत, ब्रिटिश राजतंत्र की गुलामी से आजाद हुआ था। राजदंड राजतंत्र की पहचान है। दंड की व्यवस्था राजा को विशेष अधिकार संपन्न बनाती थी। भारत में चुंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था 1950 से लागू है। जिसके कारण सत्ता स्थानांतरण के प्रतीक के रूप में मिला राजदंड कभी संसद में स्थापित नहीं किया गया। आजादी के अमृत काल में जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। संसद का नया भवन बनाया गया है। उसमें राजदंड के रूप में (सैंगोल) को हिंदू धार्मिक परंपरा के विधि विधान से, स्थापित किया जा रहा है। इससे एक बार फिर लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र लागू करने की अटकलें शुरू हो गई हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की वृद्धि दर हो सकती है 7 फीसदीः एसबीआई

नई दिल्ली । भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023 में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर को पार करने की राह पर है। भारतीय स्टेट बैंक की शुक्रवार को जारी शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही में भारत की वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत रहने की संभावना है, जिससे वित्त वर्ष 23 के लिए देश की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत हो जाएगी। यह जनवरी में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की जारी अग्रिम अनुमानों के अनुरूप है, जिसमें 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

डॉलर की बादशाहत को अन्य प्रमुख मुद्राओं से मिल रही चुनौती

लंदन । अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक 2022 की चौथी तिमाही में दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा 20 साल के निचले स्तर 58 फीसदी पर आ गया। अब यह और घटकर 1995 के समान स्तर पर आ गया है। अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को अन्य प्रमुख मुद्राओं से चुनौती मिलने लगी है। इसकी वजह खुद अमेरिकी नीतियां हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता, यूक्रेन युद्ध के झटके और अमेरिकी कर्ज संकट ने दुनिया की प्रमुख मुद्रा के रूप में डॉलर की स्थिति पर फिर से विचार करने पर मजबूर किया है। कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर का विकल्प तलाश रही हैं। रूस, चीन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश इनमें शामिल हैं। बांग्लादेश जैसे दर्जन भर छोटे एशियाई देश भी स्थानीय मुद्रा में आपसी व्यापार कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल जारी है। भारत यूएई दिरहम व रूबल में रूसी तेल खरीद रहा है। चीन ने युआन से 88 अरब डॉलर का रूसी तेल, कोयला और धातु खरीदा। वैश्विक विदेशी मुद्रा लेनदेन में युआन की हिस्सेदारी बढ़कर 7 फीसदी पर पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक 2022 की चौथी तिमाही में दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा 20 साल के निचले स्तर 58 फीसदी पर आ गया। अब यह और घटकर 1995 के समान स्तर पर आ गया है।

मेटा ने फिर निकाले कई कर्मचारी

न्यूयॉर्क । फ़ेसबुक की मालिक मेटा प्लेटफॉर्म इंक ने अपने व्यवसाय और संचालन इकाइयों में नौकरियों को कम कर दिया है। कंपनी छंटनी के तीन-भाग के अपने अंतिम बैच को अंजाम दिया, जो मार्च में घोषित 10,000 भूमिकाओं को खत्म करने की योजना का हिस्सा था। विपणन, साइट सुरक्षा, उद्यम इंजीनियरिंग, कार्यक्रम प्रबंधन, सामग्री रणनीति और कॉर्पोरेट संचार जैसी टीमों में काम करने वाले दर्जनों कर्मचारियों ने घोषणा की कि उन्हें हटा दिया गया है। बताया जा रहा है` कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने गोपनीयता और अखंडता पर केंद्रित अपनी इकाइयों से भी कर्मचारियों की छंटनी की है। 11,000 से अधिक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद मेटा ने इस साल की शुरुआत में बड़े पैमाने पर छंटनी के दूसरे दौर की घोषणा की थी। ऐसा करने वाली ये पहली बड़ी टेक कंपनी बन गई थी। कटौती ने कंपनी के हेडकाउंट को नीचे ला दिया है। 2020 के बाद से अपने कार्यबल को दोगुना करने वाली भर्ती की होड़ के बाद यह किया जा रहा है।

टाटा मोटर्स का एक लाख इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री का लक्ष्य

मुंबई । (एजेंसी)

वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स को घरेलू यात्रा वाहनों खासकर एसयूवी की बिक्री चालू वित्त वर्ष में भी मजबूत बने रहने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स पैसेंजर वेहिकल्स लिमिटेड और टाटा पैसेंजर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रबंध निदेशक शैलेष चंद्रा ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी ने एक लाख इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री का लक्ष्य रखा हुआ है। पिछले साल यह आंकड़ा करीब 50,000 ई-वाहन का था। चंद्रा ने कहा` कि मांग बने रहने के स्तर पर अभी तक संकेतक अच्छे हैं। हालांकि रुकी हुई मांग सामने आने और तैयार वाहनों की कम संख्या से मिलने वाले लाभ अब कम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों घटकों के नहीं रहने के बावजूद टाटा मोटर्स के वाहनों के लिए ग्राहकों का रुझान कायम है। उन्होंने कहा कि पहली बार वाहन खरीदने वाले के अलावा नई गाड़ी लेने वालों के बीच एसयूवी की मांग बहुत अधिक है। चंद्रा ने कहा कि महज दो साल पहले तक घरेलू वाहन उद्योग का आकार 30 लाख वाहनों का बताया जा रहा था लेकिन पिछले साल ही यह 39 लाख के आगे निकल गया। उन्होंने कहा कि इस साल अगर यह 41 लाख इकाई पर भी बना रहता है तो बहुत अच्छी वृद्धि होगी।

अलीबाबा ने 15,000 कर्मचारियों की भर्ती की बनाई योजना

नई दिल्ली । चीन की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने 15,000 लोगों को काम पर रखने की योजना बनाई है। दिग्गज चीनी टेक्निकल ग्रुप नौकरी में कटौती की रिपोर्ट को नकार रहा है। हाल ही में जारी एक बयान में चीनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने कहा कि इसके छह प्रमुख बिजनेस डिवीजन को कुल मिलाकर 15,000 नई भर्तियों की आवश्यकता होगी। कंपनी ने कहा कि वह 3,000 स्नातकों की भर्ती करेगी। चीनी टेक फर्म ने कर्मचारियों की छंटनी की खबरों को अफवाह बताया और कहा कि कर्मचारियों का निकलना एक नॉर्मल इन्फलो का हिस्सा है। ब्लूमबर्ग ने इस सप्ताह की शुरुआत में बताया था कि अलीबाबा के क्लाउड डिवीजन ने नौकरी में कटौती का दौर शुरू कर दिया है। इस छंटनी की प्रक्रिया के दौरान कंपनी के कर्मचारियों की संख्या लगभग 7 फीसदी कम हो सकती है। गौरतलब है कि कंपनी अलीबाबा एंपायर को अन्य हिस्सों में ट्रांसफर की पेशकश कर रही है, क्योंकि यह स्पिनऑफ़ और आईपीओ की पेशकश के लिए तेजी से बढ़ती क्लाउड यूनिट तैयार कर रही है। ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी ने कहा है कि वह अपने ऑपरेशन का छह-तरफा विभाजन कर रही है।

भारत में अगले 18 महीनों में सूचीबद्ध हो सकता है आरईआईटीः सीबीआरई

सिंगापुर । भारत में इस साल की दूसरी छमाही से अगले साल के ओ खिर तक कम से कम चार रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) के सूचीबद्ध होने की संभावना है। सीबीआरई इंडिया ने यह बात कही। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि यह शेयर बाजारों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। आरईआईटी विश्व स्तर पर एक लोकप्रिय निवेश साधन है और भारत में कुछ साल पहले इसे रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए पेश किया गया था। यह बड़ी रियल एस्टेट संपत्तियों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को सक्षम बनाता है। सीबीआरई ने कहा` कि आरईआईटी व्यापार निश्चित रूप से बढ़ने वाला है और हम इस साल के अंत तक एक से दो आरईआईटी की उम्मीद कर रहे हैं और पाइपलाइन में भी कुछ हैं। अमेरिका स्थित सीबीआरई दुनिया के प्रमुख रियल एस्टेट सलाहकारों में से एक है। उन्होंने कहा कि चार आरईआईटी इस साल की दूसरी छमाही से 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत तक सूचीबद्ध हो सकते हैं। उसने उम्मीद जताई कि देश तेजी से वृद्धि करता रहेगा। भारत में सड़क, हवाईअड्डे, बंदरगाह, रेल, एमआरओ और लॉजिस्टिक जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास होने जा रहा है।

शेयर बाजार में रौनक लौटी, उछाल के साथ बंद हुआ बाजार

सेंसेक्स 62 हजार के ऊपर निकला , निफ्टी 18,500 के करीब

मुम्बई ।(एजेंसी)

शेयर बाजार शुक्रवार को भारी तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही लिवाली (खरीददारी) से आया है। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सूचकांक सेंसेक्स 629.07 अंक करीब 1.02 फीसदी बढ़कर 62,501.69 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 62,529.83 तक ऊपर जाने के बाद 61,911.61 तक फिसला। वहीं इसी प्रकार पचास शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 178.20 अंक तकरीबन 0.97 फीसदी ऊपर आया। यह दिन के अंत में 18,499.35 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 18,508.55 तक ऊपर उछलने के बाद 18,333.15 तक गिरा।

वहीं गत कारोबारी सत्र में भी बाजार बढ़त पर ही बंद हुआ था।

आज के कारोबार के दौरान सेंसेक्स के शेयरों में 27 शेयर लाभ के साथ ही हरे निशान पर बंद हुए। इसमें रिलायंस, सन फार्मा, एचसीएल टेक, एचयूएल, विप्रो आदि रहे। सबसे ज्यादा लाभ रिलायंस के शेयरों को करीब 2.79 फीसदी का हुआ।

वहीं दूसरी ओर केवल 3 शेयर ही नुकसान के साथ लाल निशान पर बंद हुए। इनमें भारती एयरटेल, पावर ग्रिड और एनटीपीसी के शेयर रहे। भारती एयरटेल के शेयर सबसे अधिक 0.61 फीसदी तक गिरे। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई और निफ्टी 18350 के आसपास खुला। सेंसेक्स 101.49 अंक की बढ़त के साथ 61,974.11 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 35.75 अंक की बढ़त के साथ 18,321.15 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। आज प्री-ओपनिंग में मिलाजुला कारोबार देखने को मिला है। सेंसेक्स 151.68 अंक की गिरावट के साथ 61,720.94 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 5.60 अंक की गिरावट के साथ 18,326.80 के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

एसबीआई काड्र्स पर कोर्ट ने लगाया 2 लाख का जुर्माना

- क्रेडिट कार्ड के एक्सपायर होने के बाद भी आ रहा था बिल, यूजर्स ने की थी कोर्ट में शिकायत

नई दिल्ली ।(एजेंसी)

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के एसबीआई कार्ड पेमेंट सेवा से जुड़ा मामला सामने आया है जिसमें कंपनी के गलती के चलते उस पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, दिल्ली की एक कंज्यूमर कोर्ट ने एसबीआई कॉर्ड पर पूरे दो लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। सूत्रों के मुताबिक, एसबीआई काड्र्स के खिलाफ एक कार्ड यूजर ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने कंज्यूमर कोर्ट में बताया था कि उसके द्वारा क्रेडिट कार्ड को कैंसिल करने के बावजूद लगातार बकाया बिल भेजा जा रहा था और इसमें लेट फीस के साथ जुर्माना भी लगाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि बीते 9 अप्रैल 2016 के बाद मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से लेन-देन बंद कर दिया था। उस समय कोई भी पेमेंट बकाया नहीं था। इसमें बात प्रोसेस के तहत मैंने अपने कार्ड को बंद कराने के लिए आवेदन भी दिया, जिसके बाद उसी साल सितंबर में कार्ड रद्द करने का लेटर भी मिल गया लेकिन कुछ समय बाद एसबीआई कार्ड की ओर से मेरे रजिस्टर्ड मेल पर बिल आना शुरू हो गए, मैंने इन्हें अनदेखा किया, क्योंकि मेरा कोई भी पेमेंट बकाया नहीं था लेकिन कंपनी की ओर से लगातार लेट-फीस और जुर्माना लगाया जाता रहा और 18 मई 2017 तक बिल 2,946 रुपए का हो गया। इसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में दर्ज कराई और पूरा मामला सामने रखा। क्रेडिट कार्ड एक्सपायर होने के बावजूद, ग्राहक को लगातार बिल और उसमें लेट-फीस व जुर्माना जोड़ते जाने के इस मामले को कंज्यूमर कोर्ट ने गंभीरता से लिया और एंथनी की शिकायत को सही ठहराया। अदालत ने अब इस मामले में एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि शिकायतकर्ता को सेवा देने में नाकाम रहने और उसकी क्रेडिट रेटिंग खराब होने से हुए नुकसान की भरपाई पैसे से नहीं हो सकती लेकिन ऐसा करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई बेहद जरूरी है।

एलआईसी का मुनाफा बढ़कर 13,191 करोड़ पहुंचा

नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी का मुनाफा बीते वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में पांच गुना से ज्यादा बढ़कर 13,191 करोड़ रुपए पहुंच गया. कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,409 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था. भारतीय जीवन बीमा निगम ने कहा कि कि मार्च तिमाही में उसकी कुल आमदनी घटकर 2,01,022 करोड़ रुपए रह गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,15,487 करोड़ रुपए थी। एलआईसी की पहले वर्ष के प्रीमियम से आमदनी भी मार्च, 2022 वर्ष के 14,663 करोड़ रुपए से घटकर मार्च, 2023 में 12,852 करोड़ रुपए रह गई। एलआईसी का पूरे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुनाफा कई गुना बढ़कर 35,997 करोड़ रुपए हो गया, जो 2021-22 में मात्र 4,125 करोड़ रुपए था। एलआईसी के निदेशक मंडल ने 2022-23 के लिए 10 रुपए के अंकित मूल्य के शेयर पर तीन रुपए का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है। एलआईसी का शेयर बीएसई में 0.61 प्रतिशत लाभ के साथ 593.55 रुपये पर बंद हुआ। मुनाफे की घोषणा के बाद शेयरों में भी तेजी देखी गई। बीएसई पर एलआईसी का स्टॉक 3.72 फीसदी बढ़कर 615.65 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं एनएसई पर यह 3.63 फीसदी से उछलकर 615.50 रुपए पर पहुंच गया।

बुसान में वर्ल्ड क्लामेट इंडस्ट्री एक्सपो में लोग कार बैटरी के एक विकल्प को देखते हुए। कारोबार जगत के इस एक्सपो में नई तकनीक से जुड़े ऐसे उत्पाद पेश किये गये हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो।

बाजार में हो रही पुराने सिक्कों की नीलामी या बिक्री में बैंक की कोई भूमिका नहीं होतीः आरबीआई

आरबीआई ने बताया, इस तरह ऑनलाइन सिक्के बेचने या खरीदने में लोगों को लगाया जाता है चूना

नई दिल्ली । (एजेंसी)

आजकल बाजार में पुराने नोटों और सिक्कों की नीलामी की जा रही है। आए दिन ऑनलाइन मार्केट में इन नोटों की बोली लगाई जा रही है। धीरे-धीरे इन नोटों की नीलामी का चलन बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को चेतावनी दी है। आरबीआई पहले ही कह चुका है कि पुराने सिक्के या नोटों की खबरें केंद्रीय बैंक के हवाले से आती हैं, जबकि इस प्रकार के किसी भी नीलामी या बिक्री में आरबीआई की कोई भूमिका नहीं होती है। अगर आप पुराने नोटों या सिक्कों को बेचना चाहते हैं तो आपको आरबीआई की गाइडलाइंस को जरूर पढ़ना चाहिए।

आरबीआई ने बताया कि इस तरह के ऑनलाइन सिक्के बेचने या खरीदने में लोगों को चूना लगाया जाता है। यह एक तरह से लोगों को फ्रॉड करने का तरीका है। इस तरह से लोग ग्राहकों को चूना लगाने के फिराक में रहते हैं। इस तरह की ठगी से हमेशा आपको सावधान रहना चाहिए।

आरबीआई के पास इस तरह के कई मामले आए हैं, जिसमें आरबीआई के नाम का गलत इस्तेमाल किया जाता है। इन ठगी वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोगों से चार्जेस, कमीशन या टैक्स की मांग की जाती है। लोगों से ये दावा किया जाता है कि अगर वो पुराने नोट बेचेंगे तो उनको लाखों रुपए मिलेंगे। इस तरह कि कोई भी गतिविधि में आरबीआई शामिल नहीं होती है। आरबीआई ऐसे मामलों में न शामिल रहती है ना ही उसकी तरफ से ऐसा कोई डील की जाती है। यह लोगों के विश्वास को जीतने का बस एक तरीका होता है। लोग आरबीआई पर भरोसा करते हैं, इस वजह से वो इस तरह की ठगी के शिकार हो जाते हैं।

रिलायंस ने लोटस चॉकलेट में 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी

नई दिल्ली । (एजेंसी)

एशिया के सबसे अमीर कारोबो रियों में से एक मुकेश अंबानी अपने कारोबार को लगातार बढाते जा रही है। अब इसके जरिए अंबानी के पोर्टफोलियो में एक और बड़ी चॉकलेट बनाने वाली कंपनी लोटस चॉकलेट जुड़ गई है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने इस कंपनी में 51 फीसदी की हिस्सेदारी खरीदी है और कंपनी की ओर से इसका अधिग्रहण पूरा कर लिए जाने की जानकारी शेयर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने लोटस चॉकलेट कंपनी लिमिटेड में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की ये डील 74 करोड़ रुपए में पूरी की है। रिलायंस की ओर से कहा गया है कि 24 मई से कंपनी की कमान संभाल ली गई है। ओपन ऑफर के तहत शेयरों का अधिग्रहण पूरा किया गया है। रिलायंस ने मार्केट रेग्युलेटर सेबी के टेकओवर विनियमों के अनुसार लोटस की इक्विटी शेयर पूंजी का अतिरिक्त 26 फीसदी हिस्सा हासिल करने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा की। आरआरवीएल मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है और आरआईएल समूह के तहत सभी खुदरा व्यवसायों की होल्डिंग कंपनी है। रिलायंस और लोटस के बीच इस सौदे की घोषणा बीते साल 29 दिसंबर, 2022 को की गई थी। मुकेश अंबानी की रिलायंस के साथ डील पूरी होने की खबर से चॉकलेट कंपनी के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली।

गुरुवार को कारोबार की समाप्ति पर लोटस कंपनी के शेयर1.82 फीसदी की उछाल के साथ 148.00 रुपए पर बंद हुए।

रूस और यूक्रेन युद्ध से सरकारी तेल कंपनियों के फंसे 2500 करोड़

नई दिल्ली । (एजेंसी)

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद लगी रोक की वजह से भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों के लगभग 2,500 करोड़ रुपए की राशि रूस में फंसी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने रूस में चार विभिन्न संपत्तियों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5.46 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है। इन तेल एवं गैस क्षेत्रों के परिचालन से होने वाले लाभ पर भारतीय कंपनियों को लाभांश मिलता है लेकिन पिछले साल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद लगे आर्थिक प्रतिबंधों से भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों को अब तक यह लाभांश नहीं मिल पाया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रंजीत रथ ने कहा कि हमें लगातार इन परियोजनाओं से लाभांश आय होती रहती थी लेकिन इस बार यह रूस के बैंक खातों में ही पड़ी हुई है। इसकी वजह यह है कि रूसी बैंकों को वित्तीय अंतरण की वैश्विक प्रणाली स्विफ्ट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा रूस की सरकार ने डॉलर में भुगतान पर भी पाबंदियां लगाई हुई हैं। भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों की रूस में 30 करोड़ डॉलर यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए की लाभांश आय फंसी हुई है। इस गठजोड़ में ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड शामिल हैं। भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की इकाई है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को भी करीब इतना ही लाभांश मिलने की उम्मीद है। इस लाभांश आय को रूस से लाने के विकल्पों पर गौर किया जा रहा है।

Sports

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ रक्षापंक्ति की मजबूती पर ध्यान देंगे : दीप

एडिलेड । भारतीय महिला हॉकी टीम अब ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ शनिवार को होने वाले मैच में रक्षापंक्ति पर अधिक ध्यान देगी। आगामी एशियाई खेलों की तैयारियों के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गयी भारतीय टीम की उपकप्तान दीप ग्रेस एक्का ने कहा कि टीम की सफलता के लिए रक्षा पंक्ति का मजबूत होना जरूरी है। एक्का ने कहा,'' यह देखते हुए कि हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम का सामना किया, हमने पहले तीन मैचों में विशेषकर आक्रमण के लिहाज से अच्छा प्रदर्शन किया पर हमने कुछ अधिक गोल खाये जो रक्षापंक्त की कमजोरी के कारण हुए। इसलिए अब हमें अगले मैच में अपनी रक्षापंक्त पर ध्यान देना होगा। भारतीय टीम ने अभी तक इस दौरे में आक्रामक खेल दिखाया है पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को गोल करने से नहीं रोक पायी है। एक्का ने कहा,'' इसके साथ ही अगर हमारी रक्षापंक्ती मजबूती दिखाएगी तो अग्रिम पंक्ति के लिए निडर होकर खेलना आसान होगा। इससे हम विरोधी टीम पर दबाव बना सकेंगे। इससे आने वाले टूर्नामेंटों में भी हमें लाभ मिलेगा। पिछले कुछ समय में भारतीय टीम का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है जिससे टीम को एशियाई खेलों में पदक की उम्मीद है।

एएफसी एशियाई कप से पहले लगातार खेलने से लाभ होगा : गुरप्रीत

नई दिल्ली ।

भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने कहा कि अगले साल होने वाले एएफसी एशियाई कप से पहले लगातार अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलना खिलाड़ियों के लिए अच्छा है। इससे उनका मनोबल और कौशल बढ़ता है। गुरप्रीत ने कहा कि उनके और साथी खिलाड़ी अमरिंदर सिंह के बीच प्रतिस्पर्धा है पर उनका लक्ष्य अहम मैच जीतना है। इस साल की शुरुआत में इंफाल में तीन देशों के टूर्नामेंट में भारत ने म्यामां को 1-0 से और किर्गिस्तान को 2-0 से हराकर खिताब जीता था और टूर्नामेंट में गुरप्रीत और अमरिंदर दोनों ने इसमें संयुक्त रूप से 'टूर्नामेंट के गोलकीपर' का पुरस्कार जीता था। गुरप्रीत ने कहा, ''खिलाड़ियों के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। टीम में स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा है पर हम भाइयों की तरह हैं और हम सभी जानते हैं कि हमारे में से कोई भी किसी निश्चित दिन टीम के लिए काम कर सकता है।'' उन्होंने कहा, ''देश के लिए खेलना सबसे अधिक सम्मान की बात है और जब भी अवर मिले हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है। हम सभी की इच्छा टीम को जीतते हुए देखने की है, केवल मैदान पर रहने की नहीं।'' गुरप्रीत का मानना है कि एशियाई कप से पहले लगातार टूर्नामेंट खेलना भारतीय टीम के लिए 'बहुत अच्छा' है। टीम कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने की तैयारी कर रही है जिसमें - भुवनेश्वर में इंटरकॉन्टिनेंटल कप, बेंगलुरू में सैफ चैंपियनशिप, थाईलैंड में किंग्स कप (सितंबर) और मलेशिया में मर्डेका कप (अक्टूबर) शामिल हैं। कतर में जनवरी-फरवरी में होने वाले एशियाई कप की तैयारी कर रही भारतीय टीम इंटरकॉन्टिनेंटल कप से पहले भुवनेश्वर में प्रशिक्षण शिविर में कड़ी मेहनत कर रही है। गुरप्रीत का मानना है कि यह खिलाड़ियों के लिए अपने कौशल को बेहतर बनाने का अच्छा मौका है।

भारतीय टीम ने जापान को 3-1 से हराया

जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट

मस्कत ।

ओमान में जारी जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने जापान को 3-1 से हरा दिया। इस मैच में भारतीय टीम ने शुरुआत में एक गोल से पीछे होने के बाद शानदार वापसी कर जीत दर्ज की। भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने पूल ए के दूसरे मैच में एक गोल से पिछडने के बाद अच्छी वापसी करते हुए मुकाबला जीता। इस मैच में भारतीय टीम की ओर से अराइजीत सिंह हुंडल ने 36 वें , शारदानंद तिवारी ने 39वें और उत्तम सिंह ने 56 वें मिनट में गोल किये। वहीं जापान की ओर से कुंपेइ यासुडा ने 19वां ने गोल दागा। इस प्रकार भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरा मुकाबला जीता है। इस मैच में भारतीय खिलाडियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहले ही मिनट से हमले शुरु कर दिये। जापान ने हालांकि मुकाबले में पहला गोल किया। पहले क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर पायी। वहीं दूसरे क्वार्टर में जापान की ओर से यासुडा ने एक गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। एक गोल से पीछे होने के बाद भारतीय टीम की ओर से अराइजीत ने एक गोल दाग कर मैच 1-1 से बराबरी पर ला दिया। इसके बाद भारतीय टीम को लगातार पेनल्टी कॉर्नर मिले जिस पर शारदानंद ने गोल करके उसे 2-1 से आगे कर दिया।

इसके बाद अंतिम क्वार्टर में उत्तम सिंह ने पेनल्टी पर एक गोल करके स्कोर 3-1 कर दिया।

फिनलैंड में अभ्यास करेंगे नीरज

नई दिल्ली । विश्व के शीर्ष भालाफेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को अगले माह जून में होने वाले बड़े टूर्नामेंटों के लिये फिनलैंड में अभ्यास की अनुमति मिल गयी है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अनुसार ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज फिनलैंड के कुओर्ताने ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर में अभ्यास करेंगे। नीरज ने साल 2022 में भी वहां अभ्यास किया था। वहीं अन्य प्रस्तावों में मिशन ओलंपिक सेल ने टेबल टेनिस खिलाड़ी पायस जैन के ताईवान में अभ्यास के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। दूसरी ओर अनुभवी महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और साथियान ज्ञानशेखरन को निजी कोचों को अलग-अलग टूर्नामेंटों में साथ ले जाने को भी अनुमति मिल गयी है। इसमें वित्तीय सहायता में हवाई यात्रा का खर्च, शिविर का खर्च, रहने और चिकित्सा बीमा के खर्च के अलावा आउट आफ पॉकेट भत्ता भी शामिल रहेगा।

फ्रेंच ओपन में अल्काराज़ खेलेंगे क्वालिफायर से, जोकोविच और एलेक्जेंडर में होगी टक्कर

पेरिस ।

फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के लिए ड्रॉ जारी हो गया है। इसमें विश्वक के नंबर एक खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्काराज़ और पूर्व नंबर एक खिलाड़ी रहे सर्बिया के नोवाक जोकोविच के बीच सेमीफाइनल में मुकाबला हो सकता है। इसमें अल्काराज अपने अभियान की शुरुआत एक क्वालिफायर खिलाड़ी के खिलाफ करेंगे जबकि जोकोविच का मुकाबला पहले चरण में अमरीका के एलेक्जेंडर कोवासेविच से होगा। इस टूर्नामेंट में स्पेन के राफेल नडाल चोटिल होने के कारण भाग नहीं ले रहे हैं। यह साल 2004 के बाद पहली बार होगा कि जब नडाल अपने सबसे पसंदीदा टूर्नामेंट में नहीं नजर आयेंगे। वहीं कैस्पर रूड पहले चरण में क्वालिफायर खिलाड़ी का मुकाबला करेंगे। इसके अलावा क्वार्टरफाइनल में उनका मुकाबला डेनमार्क के होल्गर रूने से भी होने की संभावना है।

इस टूर्नामेंट में दानील मेदवेदेव भी एक क्वालिफायर खिलाड़ी के विरुद्ध शुरुआत करेंगे। क्वार्टरफाइनल में मेदवेदेव का मुकाबला इटली के जैनिक सिनर से हो सकता है। इसके अलावा विश्व के पांचवें नंबर के खिलाफ यूनान के स्तेफानोस सितसिपास पहले चरण में चेक गणराज्य के जिरी वेस्ली का मुकाबला करेंगे। पांचवीं वरीयता प्राप्त सितसिपास का मुकाबला क्वार्टरफाइनल में अल्काराज़ से भी हो सकता है। वहीं महिला वर्ग में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वियातेक अपना पहला मुकाबला स्पेन की क्रिस्टीना बुक्सा से खेलेंगी। स्वियातेक को क्वार्टरफाइनल में अमेरिका की कोको गौफ से भी खेलना पड़ सकता है। वहीं मौजूदा विंबलडन चैंपियन ऐलीना रिबाकिना क्वालिफायर के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी।

संक्षिप्त समाचार

ईसीबी अनुबंध छोडने पर बोले रॉय, एक ही प्रारुप खेलता हूं

लंदन । इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय ने अमरीका में मेजर लीग क्रिकेट खेलने के लिए राष्ट्रीय टीम का अनुबंध छोड़ने पर अपनी सफाई देते हुए का है कि मैं केवल एक प्रारुप में ही खेलता हूं। रॉय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में उठ रही अफवाहों पर मैं अपना रुख स्पष्ट करना चाहता हूं। वह ये कि मैं इंग्लैंड से दूर नहीं गया हूं। किसी भी पेशेवर क्रिकेटर के लिए अपने देश की ओर से खेलना सबसे अधिक गर्व की बात होती है। मैं अपने देश की ओर से आगे भी खेलते रहना चाहूंगा। रॉय ने लिखा, मैंने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास केंद्रीय अनुबंध नहीं है। मैं केवल एक ही प्रारुप में खेलता हूं। मैं अपने देश के लिए खेलने में गर्व का अनुभवी करता हूं। इंग्लैंड को आगामी डेढ़ महीने तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज खेलनी है। ऐसे में सफेद गेंद की सीरीज नहीं होनी है। इसी दौरान जुलाई अंत के दो सप्ताहों में मेजर लीग क्रिकेट होनी है। लीग में शामिल होने के लिए रॉय ने ईसीबी से बात की थी जिसके बाद उन्होंने अपना अनुबंध छोडने पर सहमति दे दी। गौरतब है कि विश्व भर में टी-20 फ्रेंचाइजी लीग की बढ़ती संख्या के बीच रॉय सहित इंग्लैंड के कई क्रिकेटरों की भारी मांग है। रॉय, टॉपले, हैरी ब्रूक, डेविड मलान, मैथ्यू पॉट्स और डेविड विले के ईसीबी के साथ वृद्धिशील अनुबंध हैं। इनसे उन्हें 66000 पाउंड सालाना मिलते हैं जो काउंटी तनख्वाह से अलग है।

डब्ल्यूटीसी के बाद मिलेगा सीनियर खिलाड़ियों को आराम

हार्दिक की कप्तानी में घरेलू सीरीज खेल सकती है युवा टीम

मुम्बई । भारतीय टीम अगले माह जून में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के बाद पड़ोसी देश अफगानिस्तान से एक घरेलू सीरीज खेलेगी। इसमें अनुभवी खिलाड़ियों की जगह युवा खिलाड़ियों को जगह मिल सकती है। इस सीरीज में टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या को मिल सकती है। इसके अलावा, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में सीमित ओवरों के प्रारूप में एक सीरीज होने की भी संभावना है। इसमें भी वरिष्ठ खिलाड़ियों को शामिल न करते हुए आराम दिया जाएगा। इस कार्यभार प्रबंधन की योजना वेस्टइंडीज दौरे को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को घरेलू सीरीज के दौरान आराम दिया जाएगा। इसके अलावा, बीसीसीआई सीरीज को कम करने पर भी विचार कर सकता है क्योंकि सीरीज के प्रबंधन के लिए केवल 20 और 30 जून के बीच की ही विंडो है। भारतीय टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर पांच टी-20, तीन एकदिवसीय और दो टेस्ट खेलेगी। यह दौरा 12 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त को समाप्त होगा। इसके बाद भारतीय टीम टी20 सीरीज खेलने आयरलैंड जाएगी।

रोहित को कप्तान के तौर पर धोनी जितना श्रेय नहीं मिला : गावस्कर

मुम्बई ।

महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा है कि मुंबई इंडियंस को सबसे अधिक पांच बार खिताब जिताने के बाद भी कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा को उतना श्रेय नहीं मिला जितना चेन्नई के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी को मिला है। गावस्कर ने कहा कि रोहित ने अपने नेतृत्व कौशल से ही एलिमिनेटर में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एक अच्छी योजना बनायी थी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार इस लीग में हार के साथ मुम्बई की शुरुआत हुई थी। उसके बाद भी रोहित ने टीम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना जारी रखा। अपने पहले सात मैचों में से चार में हारने के बाद और आईपीएल 2023 पॉइंट्स स्टैंडिंग के नीचे गिरने के बाद भी जिस प्रकार मुंबई ने प्लेऑफ में आगे बढ़ने के लिए अपने अगले सात मैचों में से पांच में जीत हासिल की यहा रोहित की कप्तानी क्षमता से ही हुआ।

गावस्कर ने रोहित की रणनीति पर कहा , जब उन्होंने एक ओवर में युवा हिटर आयुष बडोनी और विंडीज स्टार निकोलस पूरन को पेवेलियन भेजने के लिए अचानक ही आकाश मधवाल को लगाया। अगर इसी हाल में टीम सीएसके होती तब हर कोई कहता कि धोनी ने पूरन को आउट करने की साजिश रची। बहुत हद तक ऐसा ही होता है।गावस्कर ने कहा, मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि रोहित को मधवाल को राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए कहने का श्रेय नहीं मिला। कप्तानी की स्थिति का भी नहीं मिला। याद रखें, नेहल वढेरा को पहले बल्लेबाजी करने वाले इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

जब टीमें पहले बल्लेबाजी कर रही होती हैं तो वे आम तौर पर बल्लेबाजों को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल नहीं करती हैं। लेकिन रोहित ने नेहल का इस्तेमाल किया। इसलिए रोहित को इसका श्रेय भी दें।

डब्ल्यूटीसी विजेता टीम को मिलेंगे 13.21 करोड़ , उपविजेता को 6.50 करोड़ रुपए : आईसीसी

दुबई । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगले माह जून में होने वाली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल की विजेता टीम को 16 लाख डॉलर करीब 13.21 करोड़ रुपये का इनाम मिलेगा। वहीं उप-विजेता टीम को 800,000 डॉलर (6.50 करोड़ रुपए) मिलेंगे। चैंपियनशिप का फाइनल लंदन के द ओवल, में 7 से 11 जून तक खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट की ईनामी राशि उतनी ही है जितनी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2019-21 की थी। उस समय न्यूजीलैंड की ने 16 लाख डॉलर ईनामी राशि जीती थी। इसके अलावा विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की कुल 38 लाख डॉलर ईनामी राशि में से सभी नौ टीमों को हिस्सा मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका को तीसरे स्थान पर रहने के लिये 450000 डॉलर करीब 3 करोड़ 72 लाख मिलेंगे जबकि इंग्लैंड को चौथे स्थान पर रहने के 350000 डॉलर तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख मिलेंगे। श्रीलंका को पांचवें स्थान पर रहने के लिए दो लाख डॉलर यानी कि करीब 1 करोड़ 65 लाख दिए जाएंगे। वहीं बची हुई टीमों को एक-एक लाख डॉलर करीब 82 लाख रूपए मिलेंगे ।

फाइनल 2023 के लिए भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीम इस प्रकार है :

भारतीय टीम : रोहित शर्मा (कप्तान), शुबमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, केएस भरत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनादकट।

स्टैंडबाय खिलाड़ी: ऋतुराज गायकवाड़, मुकेश कुमार, सूर्यकुमार यादव।

ऑस्ट्रेलियाई टीम : पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स केरी, कैमरन ग्रीन, मार्कस हैरिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मारनस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिशेल मार्श, टोड मर्फी , मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ (उपकप्तान), मिशेल स्टार्क और डेविड वार्नर।

सिंधु मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंची, श्रीकांत बाहर हुए

कुआलालंपुर । भारत की महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने महिला एकल क्वार्टर फाइनल में अपने से निचली रैंकिंग वाली चीन की यि मान झांग को 21-16, 13-21, 22-20 हराया। दूसरी ओर पुरूष एकल के एक अन्य मुकाबले में भारत के ही किदाम्बी श्रीकांत को इंडोनेशिया के क्वालीफायर क्रिस्टियन एडिनाटा के हाथों 16-1, 21-16, 21-11 से हार का सामना करना पड़ा है। महिला एकल की बात करें तो विश्व रैंकिंग में 13वें स्थान पर बरकरार सिंधु ने इस जीत के साथ ही 18वीं रैंकिंग वाली झांग से ऑल इंग्लैंड ओपन में मिली हार का हिसाब भी बराबर कर लिया। अब अंतिम चार में सिंधु का मुकाबला विश्व की नौवें नंबर की खिलाड़ी इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का टी से होगा। मारिस्का ने एक अन्य मुकाबले में चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त यि झि वांग को 21-18, 22-20 से हराया।

लगा था पदक विजेता खिलाड़ी होने के कारण हमारी बात सुनी जाएगी पर ऐसा नहीं हुआ : बजरंग

नई दिल्ली ।

ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया पिछले काफी दिनों से कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। बृजभूषण पर पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाये हैं। इसके बाद भी बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से ये पहलवान निराश हैं। बजरंग के अनुसार शुरुआत में उन्हें लगता था कि पदक विजेता अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी होने के कारण उनकी बात सुनी जाएगी और धरने पर बैठने तक की नौबत नहीं आयेगी पर उनका भरोसा गलत साबित हुआ। इसके साथ ही अपनी मांगों को लेकर यहां धरने पर बैठे कई अन्य लोगों को देखकर भी बजरंग दुखी हैं उन्होंने कहा कि हमें ही नहीं अन्य कई लोगों को भी परेशानियां हैं जिसका अब हमें अहसास हुआ है। अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर बजरंग ने कहा 'हमें ये कभी भी नहीं लगा था कि हमारे इतने सारे पदक जीतने के बाद भी हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी पर हकीकत कुछ और ही है।' गौरतलब है कि बृजभूषण भाजपा सांसद हैं और माना जा रहा है कि इसी कारण उनके खिलाफ अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं।

बजरंग ने अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा, 'हम जानते हैं कि हम किसके खिलाफ हैं लेकिन हम डरते नहीं हैं।' पुनिया ने ये भी कहा कि जब दिसंबर में उन्होंने विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ विरोध प्रदर्शन का फैसला किया था तो आगे की सभी कठिन संभावनाओं के बारे में सोचा था पर जिस तरह से अब चीजें सामने आ रही हैं। वो उनके दायरे बाहर हैं।

गत एक माह से अधिक समय से धरने पर बैठे बजरंग ने कहा कि हम जानते थे कि हमारा करियर समाप्त हो सकता है। हम जानते थे कि धरने पर बैठने के बाद कोचिंग या प्रशासन जैसे करियर के बाद विकल्प हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा हमें झूठे मामलों में भी फंसाया जा सकता है पर बाद में लगा कि जब कारण वास्तविक हो और संकल्प मजबूत हो तो डरने की कोई जरुरत नहीं होती। यह एक कठिन फैसला था पर पहलवान होने के कारण हम बिना लड़े हार नहीं मानते।

कैफ, इरफान और शास्त्री ने मधवाल की जमकर प्रशंसा की

मुम्बई ।

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में शानदार गेंदबाजी कर सबका ध्यान खींचने वाले मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज आकाश मधवाल एक मैच से ही स्टार बन गये हैं। तीन पूर्व क्रिकेटर ने आकाश की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्होंने एक दबाव भरे मैच में अपने को साबित किया है। पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने मधवाल की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके कारण ही मुम्बई हो जीत मिली। कैफ ने कहा कि मधवाल की गेंदबाजी शैली तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से मिलती जुलती है, उन्होंने कहा कि वह लखनऊ के खिलाफ अपने प्रदर्शन के लिए सभी की प्रशंसा के अधिकारी हैं। मधवाल ने एलिमिनेटर में अपने चार ओवरों में केवल पांच रन देकर पांच विकेट लिए। कैफ ने कहा, आकाश खतरनाक लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। उनकी गेंदबाजी शैली शमी से काफी मिलती है। वह हाल ही में मुंबई इंडियंस के लिए खास खिलाड़ी रहे हैं। वह हर खेल के साथ एक परिपक्व गेंदबाज की तरह दिखता है।वहीं पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा कि उन्होंने आईपीएल में कभी भी किसी अनकैप्ड खिलाड़ी को इतनी दबाव वाली स्थिति में हावी होकर गेंदबाजी करते नहीं देखा। मधवाल ने आईपीएल 2023 में 13 विकेट लिए हैं और एमआई को दूसरे क्वालीफायर में प्रवेश दिलाया। आकाश ने पिछले दो मैचों में 9 विकेट लिए हैं। मुंबई को क्वालीफायर में ले जाने का श्रेय उन्हें देना ही होगा।वहीं पूर्व क्रिकेटर और कोच रहे रवि शास्त्री ने कहा कि टेनिस गेंद से खेलने वाले क्रिकेटर बहुत चालाक होते हैं और मधवाल ने बड़े मंच पर वह कौशल दिखाया है। उन्होंने कहा, मधवाल ने अपने को इस खेल में शानदार ढंग से लागू किया। उन्होंने सुंदर गेंदबाजी की और धीमी चेपॉक ट्रैक पर कठिन लेंथ पर गेंदबाजी की। उनके पास एक अच्छा कटर भी है, उन्होंने अपने शानदार गेंदबाजी कौशल से सबको हैरान किया है।

बगीचा

स्थापना व प्रबंधन

नवीन उद्यान का विन्यास (लेआउट) कैसे करें

नवीन उद्यान का विन्यास (रेखांकन) एक बहुत तकनीकी एवं महत्वपूर्ण क्रिया है। सर्वप्रथम क्षेत्रफल नाप लिया जाये तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें फिर चयनित फल एवं उसकी प्रजाति के आधार पर निर्धारित करें कि कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी निर्धारित करें। उद्यान रेखांकन करते समय निम्नलिखित उद्यान स्थल निर्धारित करें

सड़क एवं मार्ग

- फार्म हाउस (कार्यालय, भंडार, निवास) के लिए स्थल
- सिंचाई पद्धति के लिये पम्प हाउस, नलकूप, कुआं, फार्म पॉंड का स्थान निर्धारित करें। आजकल ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई प्रचलित है। अत: उसके रेखांकन के लिये स्थल निर्धारित करें।
- जल निकास हेतु नाली आदि निर्माण हेतु स्थल
- पौधों को लगाने का स्थल
- फार्म पर कम्पोस्ट, नाडेप, केंचुआ खाद आदि का स्थल
- बगीचे के लिये स्वयं की रोपणी हेतु भी स्थल निर्धारित करें।
- नवीन बगीचे के लिये प्रारंभिक तैयारियां – स्थल निर्धारण के पश्चात भूमि की सप्लाई, सर्वेक्षण, मिट्टी परीक्षण, समतलीकरण, मिट्टी की जुताई, बगीचे के चारों ओर बागड़–तार, पत्थर की दीवार, वायु अवरोध लगाएं.

फल पौध रोपण

फल पौध रोपण की प्रचलित पद्धतियां निम्न प्रकार की है
वर्गाकार पद्धति – वृक्ष की आवश्यकता के अनुसार वर्ग का आकार रखा जाता है। इस पद्धति में पौधे वर्ग के कोने पर लगाए जाते हैं।
आयताकार– इस पद्धति में कतार से कतार की दूरी तथा पौधों की दूरी निर्धारित की जाती है॥
त्रिभुजाकार या षटभुजाकार पद्धति।
पंचवृक्षीया गौपूरक पद्धति– यह वर्गाकार की परिवर्तित पद्धति है इसके वर्ग के मध्य से एक और पौधा बनाया जाता है।
आजकल संकर प्रजातियां आम में विकसित की गयी है उन्हें कम दूरी पर बनाया जाता। इसके अतिरिक्त हाईडेन्सिटी पद्धति से रोपण ऊंचाई के आधार पर किया जाता है।
कंटूर के आधार पर रोपण – ऊंची–नीची एवं ढाल भूमि में समोच्च (कन्टूर) के आधार पर रोपण किया जाता है।

पौधों की दूरी निर्धारित करना एवं वृक्षों की वृद्धि को ध्यान में रखकर पौध रोपण के लिये गड्ढों का खोदना – यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। भूमि में मिट्टी की गहराई को ध्यान में रखते हुए फल चयन करें तथा उसकी भावी वृद्धि एवं विकास को ध्यान में रखते हुए रोपण के लिए

गड्ढे वर्गाकार पद्धति से या मिट्टी आकार द्वारा खोदें।

रोपण के लिये पौधों का चयन

- पौधे जो वानस्पतिक तरीके या टिशू कल्चर अथवा बीज से तैयार हो उनकी पूरी विश्वसनीयता की जानकारी प्राप्त करके ही लें। उनकी पे डिग्री ज्ञात कर लें. जब तक शासकीय/ पंजीकृत रोपणी से ही पौधे लें तथा पौधों पर टैग लगा हो।
- प्रत्येक पौधे को देखें कि उसकी जूटी जिसमें पौधों की जड़ पंकी हो वह सही हो। ग्राफ्ट की जड़े सायन एवं रूट स्टाक की मोटाई बराबर हो तथा सही तरीके से जुड़ी हों।
- पौधे की बीमारी आदि से ग्रसित न हों। उनकी आयु आदि ज्ञात कर लें।
- जो पौधे चाहे ग्राफ्ट हो,गूटी कलम आदि जैसे भी हो उन्हें भली–भांति परख लें तथा एक सप्ताह तक क्यारी में उतार कर रखें। जो पौधे सही तरह के स्वस्थ हों उन्हें ही लगायें।
- पौधे लगाते समय पौधा गड्ढे के बीज में सीधा लगाया जाये। जड़ को दोनों हाथों से ढीला बांध भली–भांति गड्ढे की मिट्टी के साथ दवाएं जिससे वह भली–भांति स्थिर हो जावे सिंचाई करें। रोपण क्रिया जुलाई, अगस्त, सितम्बर या फरवरी मार्च में लगायें। उसकी सुरक्षा करें तथा कुछ पौधे पृथक रखें जिससे मृदा पौधों के स्थान पर रोपण करें।

फल देने वाले बगीचों का प्रबंधन

जो पौधे फलन स्थिति या किशोर अवस्था में हो उनकी देखभाल एवं वांछित औद्योगिक क्रियाएं क्षेत्र के लिये अनुशंसित विधि से करें। जैसे– कांटछांट का कृन्तन क्रिया कृषि क्रियाएं अनुशंसित खाद एवं उर्वरक निर्धारित मात्रा में डालें, तने को पानी के सम्पर्क में सीधे न आने दें इसलिये उनकी आयु के अनुसार मिट्टी जड़ के ऊपर लगाये, समय पर सिंचाई, निंदाई तथा पौध संरक्षण उपाय करें। फलों की तुड़ाई करें। आम के वृक्षों पर माम फोर्मेशन हो उसे काटकर पृथक करें। जिन पौधों के तने कमजोर हो उन्हें सहारा दें। पौधे के मूल वृन्द से निकलने वाली शाखाओं को काट दें। पौधोंको सही आकार देने के लिए कटाई, छंटाई जरूरी है।

रामतिल सुरक्षित फसल

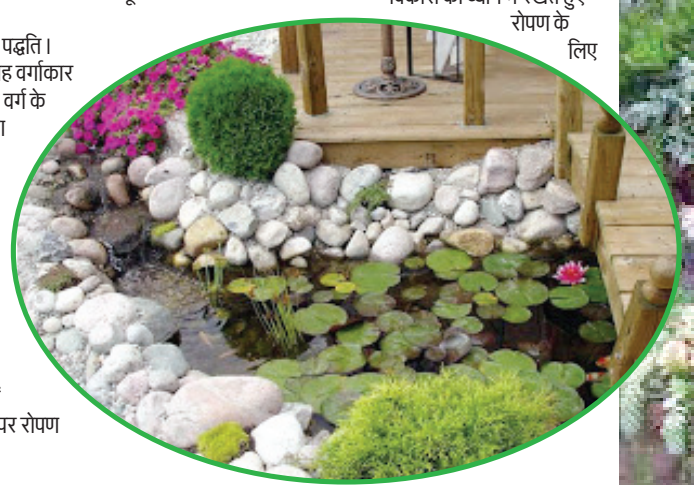

भारत में इस फसल की खेती 5.42 लाख हेक्टेयर में प्रतिवर्ष की जाती है। इसकी औसत उत्पादन क्षमता 299 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कुल उत्पादन 1.62 लाख टन प्रतिवर्ष होता है। अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य रामतिल के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्य था। डिण्डोरी जिले में लगभग 35 हजार हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है जिसका औसत उत्पादन 200 कि.ग्राम प्रति हेक्टेयर है। यदि फसल को अच्छे प्रबंधन के साथ लगाया जाए तो उपज 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जाती सकती है। अनुकूल उत्पादन अवस्थाओं में इसका उत्पादन 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के अच्छे उत्पादन प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि कृषक उन्नतशील किस्मों का प्रयोग करें। मौसम के अनुसार उपयुक्त समय पर बुआई करें।
भूमि का चुनाव– यह फसल गहरी काली मिट्टी से भुरभुरी, रेतीली भूमियों जिसमें जल निकास की उत्तम क्षमता हो, में सफलतापूर्वक लगाई जा सकती है। अच्छी गहराई वाली मिट्टी जिसका पी.एच. मान 5.5 से 6.5 के बीच हो इस फसल के लिए अति उत्तम मिट्टी होती है।

हल्की क्षारीय एवं लवणीय भूमि में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। परंतु भारी काली कपास वाली भूमि एवं पानी रुकने वाली भूमियां इसके खेती हेतु उपयुक्त नहीं है।
फसल पद्धति –रामतिल फसल की बुआई सामान्यत: मध्य अगस्त में की जाती है। अत: इसके पूर्व एक फसल उड़द, बरबटी या फ्रेंचबीन की ले सकते हैं। डिंडोरी जिले में इस फसल को कुटकी की फसल लेने के बाद भी लेने की संभावना है। परंतु इसके लिये यह आवश्यक होगा कि पहली फसल की बुआई मई के अंत में या जून के प्रथम सप्ताह तक पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि देर से बुआई करने पर रामतिल की बुआई में देरी होगी जिसका उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
उन्नत किस्में – अच्छी उपज लेने के लिए उपयुक्त किस्म का चयन किया जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भूमि एवं बोने के समय के अनुसार उपयुक्त किस्म का चुनाव करना चाहिए। अखिल भारतीय समन्वित तिल एवं रामतिल अनुसंधान परियोजना के द्वारा अनेक उन्नत किस्मों की अनुशंसा की गई है। डिंडोरी क्षेत्र के लिये अनुशंसित किस्म के प्रमुख गुण एवं लक्षण तालिका में प्रस्तुत हैं।
बीज दर – शुद्ध फसल हेतु 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है।

बीजोपचार –
फसल को बीज एवं मिट्टी जनित रोग के संभावित आक्रमण को टालने के लिए बीजोपचार आवश्यक है। थायरम या केप्टान नामक दवाई की 3 ग्राम मात्रा से एक किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। बुआई के 12 घंटे पूर्व

फास्फोरस घोलक जीवाणु (पी.एस.बी.) कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर उपचारित कर छायादार स्थान में सुखाना चाहिए, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है।
बुआई विधि –सामान्यत: रामतिल की बुआई छिड़काव पद्धति से की जाती है इससे प्रति क्षेत्र में वांछित पौध संख्या नहीं मिल पाती है। इसकी अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कतार से बुआई करना चाहिए एवं एक कतार से दूसरे कतार के बीच में 30 से.मी. (1 फीट) का अंतर होना चाहिए। बुआई के पूर्व एक भाग बीज को 20 भाग रेत या भुरभुरी गोबर खाद या राख के साथ मिलाकर बुआई करना चाहिए। इससे प्रति इकाई क्षेत्र में वांछित पौधा संख्या प्राप्त होगी एवं पौध छंटाई का कार्य नहीं करना पड़ता।
उर्वरक एवं खाद – रसायनिक उर्वरकों में नत्रजन 10 किलोग्राम, स्फुर 20 किलोग्राम एवं पोटाश 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के समय डालना चाहिए। बुआई के 30 से 35 दिन बाद 10 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की मात्रा भूमि में नमी उपलब्ध पर डालने से उत्पादन में वृद्धि होती है।
नींदा नियंत्रण – रामतिल फसल में पहली निंदाई – गुड़ाई बुआई के 15–20 दिन बाद करना चाहिए। यदि आवश्यक है तो दूसरी निंदाई –गुड़ाई बुआई के लगभग 35 – 40 दिन बाद करें। यह कार्य खड़ी फसल में नत्रजन के छिड़काव से पहले कर लेना चाहिए। रामतिल की फसल से डिण्डोरी क्षेत्र में अमरबेल की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। जिसके कारण कृषक बंधु इसकी खेती को छोड़ रहे है परंतु अनुसंधान के आधार पर रसायनिक दवा के उपचार से अमरबेल का समूल नाश किया जा सकता है। इसके लिए नींदानाशक दवा पेन्डीमिथालीन 0.75 से 1.5 किलो सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए अथवा लासो दानेदार 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।
कटाई एवं गहाई – रामतिल की फसल किस्मानुसार 90 से 120 दिनों के बीच पककर तैयार हो जाती है। जब पौधे की पत्तियां सूखकर गिरने लगे एवं फली का शीर्ष भाग भूरे एवं काले रंग का दिखने लगे तब फसल की कटाई करें। कटाई में देर करने पर बीज झड़ने का डर रहता है। कटाई के उपरांत पौधों को बंडल में बांधकर खेत में खुली धूप में एक सप्ताह तक सुखाकर गहाई करनी चाहिए।
आय – व्यय –परम्परागत तरीके से फसल लगाने से उपज 50 से 200 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। जिससे कुल आमदनी 2250 से 9000 रु. होती है। उन्नत काश्त तकनीक अपनाकर खेती करने से औसत उपज 500 से 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होगी जिससे कुल आय 20,000 से 25000 रु. तक प्राप्त होगी।

विमान जैसे ही उड़ान भरा, एक यात्री ने खोला दरवाजा, विमान में भर गई हवा

-प्लेन में सवार 194 यात्रियों की जान पर आ गई

सियोल । दक्षिण कोरिया के एक विमान के उड़ान भरने के दौरान एक यात्री ने शुक्रवार को आपातकालीन दरवाजा खोल दिया, जिससे केबिन के अंदर हवा भर गयी।हालांकि, विमान बाद में सुरक्षित उतर गया।एअरलाइन और सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर शेयर किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया के परिवहन मंत्रालय ने बताया कि एशियाना एयरलाइंस एयरबस ए-321 विमान में सवार कुछ लोगों ने उस व्यक्ति को दरवाजा खोलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह आंशिक रूप से खुल गया था। एशियाना एयरलाइंस के अनुसार विमान 194 यात्रियों के साथ दक्षिणपूर्वी शहर दाएगू से दक्षिणी द्वीप जेजु जा रहा था।इस बात की जांच की जा रही है कि दरवाजा कितनी देर खुला रहा। विमान का दरवाजा खुलने की घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हवा के कारण कुछ यात्रियों के बाल उड़ते हुए देखे गए। एयरलाइन ने बताया कि पुलिस ने दरवाजा खोलने वाले अज्ञात व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। इस घटना से कुछ यात्री डर गए, लेकिन किसी को भी चोट नहीं आयी। हालांकि, कुछ यात्रियों की अस्पताल में जांच की गयी। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस घटना के बाद 9 यात्रियों को पास के एक अस?पताल में ले जाया गया है। इन लोगों को सांस लेने में दिक ?कत हो रही थी। अच?छी बात यह रही कि सभी यात्री अपनी सीट पर बैठे हुए थे और उन?होंने सीट बेल?ट लगा रखा था। यह विमान उतरने वाला था।

चीन में जून तक हर सप्ताह आ सकते हैं कोरोना के 6.5 करोड़ मामले

बीजिंग । चीन में कोरोना की नई लहर देखी जा रही है, जिसमें जून के आखिर तक हर हफ्ते 6.5 करोड़ मामले आ सकते हैं। चीन के नेशनल क्लीनिकल रिसर्च सेंटर फॉर रेसपिरेटरी डिजीज के निदेशक झोंग नानशान की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है।जून तक चीन में साढ़े छह करोड़ लोग हर हफ्ते कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। सरकारी अधिकारी नवीनतम ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए अपने वैक्सीन स्टॉक को बढ़ाने में लगे हुए हैं। चीनी स्वास्थ्य अधिकारी कोरोनो की चल रही नई लहर का मुकाबला करने के लिए टीकों को आगे बढ़ाने के लिए ऐड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। बता दें कि जून में कोविड संक्रमण के चरम पर पहुंचने की उम्मीद है और एक सप्ताह में ये 65 मिलियन लोगों को संक्रमित कर सकता है। वायरस के नए एक्सबीबी संस्करण विकसित प्रतिरक्षा को दूर करने के लिए विकसित हो रहे हैं। चीन के मीडिया के अनुसार, एक्सबीबी ओमिक्रोन के बीए.2.75 और बीजे .2 सब-वैरिएंट का ही हाइब्रिड रूप है। अप्रैल के अंत से, कोरोना वैरिएंट एक्सबीबी देश भर में मामलों में वृद्धि कर रहा है और मई के अंत तक प्रति सप्ताह 40 मिलियन संक्रमण होने की संभावना है। इससे पहले कि यह एक महीने बाद 65 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।

अमेरिका में एक घर में विस्फोट होने से 3 लोगों की मौत

वाशिंगटन । अमेरिका के दक्षिण डकोटा राज्य में एक मकान में विस्फोट हो गया, जिसमें एक शिशु और उसके दादा-दादी की मौत हो गयी तथा दो अन्य बच्चे झुलस गए। दक्षिण डकोटा स्टेट फायर मार्शल का कार्यालय घटना की जांच कर रहा है और विस्फोट के कारणों का पता लगा रहा है। स्टेनली काउंटी के शेरिफ ब्रैड रथबन ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 10 बजकर 20 मिनट पर फोर्ट पियरे से करीब 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित एक मकान में विस्फोट हुआ। शेरिफ ने बताया कि छह माह के हार्पर हप और उसकी दादी लाडोना हप (61) की मौके पर ही मौत हो गयी। वहीं विलियम हप (66) की एक अस्पताल में मौत हो गयी। इस हादसे में दो बच्चे पांच साल का माइल्स और तीन साल का रॉयसे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें मिनेसोटा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त बच्चों के माता-पिता केलसी और ट्रेवर हप काम पर गए हुए थे। रथबन ने बताया कि ग्रामीण इलाके में पड़ोसियों ने विस्फोट की आवाज सुनी और प्राधिकारियों को सूचना दी। उन्होंने विस्फोट के पीछे किसी साजिश की आशंका से इनकार किया है।

सिंगापुर की निर्माण कंपनी से धोखाधड़ी करने पर भारतीय नागरिक को 30 महीने की जेल

सिंगापुर । सिंगापुर में एक निर्माण कंपनी से कथित तौर पर 51 लाख सिंगापुरी डॉलर की धोखाधड़ी करने के जुर्म में एक भारतीय नागरिक को 30 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। भारतीय नागरिक हुसैन नैना मोहम्मद (47) ने धोखाधड़ी करने और अपराध से अर्जित धनराशि का एक हिस्सा सिंगापुर से बाहर भेजने का जुर्म कबूला। खबर के अनुसार दोषी व्यक्ति ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने अपने माता-पिता के घरेलू खर्चों को पूरा करने में मदद के लिए पैसे भारत भेजे थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि मोहम्मद ने स्वीकार किया है कि उसने यूट्राकॉन कॉर्प नामक कंपनी से कुछ धनराशि हासिल करने के लिए एक कंपनी की स्थापना की थी। वह आरेट नामक कंपनी के लिए सभी व्यावसायिक निर्णय लेने वाला एकमात्र व्यक्ति था। हम्मद ने जनवरी 2019 तक निर्माण कंपनी यूट्राकॉन स्ट्रक्चरल सिस्टम्स के लिए काम किया, जो कि यूट्राकॉन कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। मोहम्मद ने अपने नियोक्ता को यह नहीं बताया कि वह आरेट में भागीदार है। इसके बजाय उसने अपने नियोक्ता से आरेट कंपनी को समुद्री बीमा के साथ-साथ माल-अग्रेषण सेवाओं के चुनने की सिफारिश की।

अगले सप्ताह भारत का दौरा करेंगे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन

वाशिंगटन । अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत के अपने समकक्ष से मुलाकात करने के लिए अगले सप्ताह नई दिल्ली जाएंगे। पेंटागन ने यह घोषणा की है। यह यात्रा अगले महीने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजकीय यात्रा से पहले हो रही है। पेंटागन ने रक्षा मंत्री की अगले सप्ताह जापान, सिंगापुर, भारत और फ्रांस की यात्रा की घोषणा की। उसने कहा कि ऑस्टिन अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा भागीदारी को मजबूत करने की कवायद के तौर पर नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेंटागन ने कहा ?कि यह यात्रा नए रक्षा नवाचार और औद्योगिक सहयोग की शुरुआत तथा अमेरिकी और भारतीय सेनाओं के बीच परिचालन सहयोग का विस्तार करने के लिए चल रहे प्रयासों में तेजी लाने का अवसर प्रदान करती है। ऑस्टिन हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अपनी सातवीं आधिकारिक यात्रा के तौर पर जापान से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। तोक्यो में उनकी योजना जापान के रक्षा मंत्री यासुकासु हमादा और अन्य वरिष्ठ नेताओं तथा जापान में तैनात अमेरिकी सैनिकों से भी मुलाकात करने की है। वहां से ऑस्टिन सिंगापुर जाएंगे जहां वह सामरिक अध्ययन के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थान (आईआईएसएस) के 20वें शंगरी-ला संवाद को संबोधित करेंगे। सिंगापुर के बाद ऑस्टिन नई दिल्ली जाएंगे और फिर फ्रांस जाकर डी-डे (नॉरमैण्डी पर हमले के 79वें वर्ष) पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

दुनिया के सबसे बदहाल देशों की सूची में पहले स्थान पर जिम्बाब्वे

-ब्राजील, पाकिस्तान, नेपाल व स्वीडन से भारत बेहतर

नई दिल्ली । दक्षिण अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे दुनिया के सबसे बदहाल देशों की सूची में पहले स्थान पर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जाने-माने अर्थशास्त्री स्टीव हैंके के एनुअल मिजरी इंडेक्स में लिखा हे कि जिम्बाब्वे आर्थिक तौर पर दुनिया का सबसे बदहाल देश है, जहां अधिकतर लोग नाखुश हैं। जिम्बाब्वे की हालात युद्ध झेल रहे यूक्रेन, सीरिया और सुडान से भी खराब है। जिम्बाब्वे आसमान छूती महंगाई से त्रस्त है, जो पिछले साल 243.8 फीसदी पर पहुंच गया था। स्टीव हैंके ने देश की बदहाली के लिए राष्ट्रपति एमर्सन मनांगवा और सत्ताधारी पार्टी जैनू-पीएफ की नीतियों को भी जिम्मेदार बताया है। हैंके की रिपोर्ट का आधार आर्थित स्थितियों के मुताबिक तय होता है। इस रैंकिंग में 157 देशों का विश्लेषण किया गया है। हैंके ने बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बैंक-उधार दरों और जीडीपी में प्रतिशत परिवर्तन जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हैंके के एनुअल मिजरी इंडेक्स की 2022 रैंकिंग की गणना की। इंडेक्स में जिम्बाब्वे के बाद वेनेजुएला, सीरिया, लेबनान, सुडान, अर्जेंटीना, यमन, यूक्रेन, क्यूबा, तुर्की, श्रीलंका, हैती, अंगोला, टोंगा और घाना का नाम टॉप-15 में शामिल हैं। इस इंडेक्स में भारत का नाम भी शामिल किया गया है। इंडेक्स में भारत को 103 रैंक पर रखा गया है। भारत ने ब्राजील (रैंक 27), पाकिस्तान (रैंक 35), नेपाल (रैंक 63) और स्वीडन (रैंक 88) जैसे देशों से बेहतर स्थिति में है।

पोचियान में अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान राकेट दागते हुए दक्षिण कोरियाई सेना।

मोदी को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने आमंत्रित करें मैक्कार्थी : अमेरिकी सांसद खन्ना

वाशिंगटन । अमेरिका के भारतीय मूल के सांसद रो खन्ना ने विश्वास जताया है कि प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) केविन मैक्कार्थी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आमंत्रित करेंगे। मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन द्वारा अगले महीने आधिकारिक राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है। 'कांग्रेसनल इंडिया कॉकस' के सह-अध्यक्ष के रूप में खन्ना ने मंगलवार को मैक्कार्थी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वह मोदी को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करें। मैक्कार्थी के साथ बुधवार को एक बैठक के बाद खन्ना ने मीडिया से कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अध्यक्ष संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए मोदी को निमंत्रण देंगे। संबोधन की तारीखों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल ने 27 अप्रैल 2023 को कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रथम महिला मोदी के सम्मान में 22 जून को राजकीय रात्रिभोज का आयोजन करेंगे।

पुतिन ने अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वार्ता में प्रगति के संकेत दिए

- पुतिन ने मॉस्को में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम और अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल से मुलाकात की

मॉस्को (एजेंसी)। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि एक विवादित क्षेत्र को लेकर लड़ रहे पड़ोसी देश अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच मुख्य विवादों में से एक को हल करने में केवल तकनीकी बाधाएं हैं। पुतिन ने मॉस्को में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव और अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान से मुलाकात की और उनसे लाचिन गलियारे को लेकर विवाद पर चर्चा की। यह अर्मेनिया और विवादित क्षेत्र नगोर्नो-काराबाख के बीच इकलौता अधिकृत संपर्क क्षेत्र है तथा क्षेत्र के करीब 1,20,000 लोगों को सामान की आपूर्ति के लिए जीवनरेखा है। मॉस्को में पुतिन की मेजबानी में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में अलियेव और पाशिनयान ने इस गलियारे को लेकर एक-दूसरे पर भड़ास निकाली। पुतिन ने कहा कि प्रमुख मुद्दों पर एक समझौता है और बाद में उन्होंने कहा कि तकनीकी मुद्दों पर विवाद हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक पाशिनयान ने कहा ?कि मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता हूं कि अर्मेनिया और अजरबैजान एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता को परस्पर मान्यता देने पर सहमत हो गए हैं और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम अपने संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं।

गौरतलब है कि अर्मेनिया और अजरबैजान ने 2020 में नगोर्नो-काराबाख को लेकर लड़ाई लड़ी थी जिसमें 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। रूस की मध्यस्थता में यह लड़ाई खत्म हुई थी। नगोर्नो-काराबाख अजरबैजान की सीमा में आता है लेकिन अर्मेनिया द्वारा समर्थित जातीय अर्मेनियाई बलों ने 1994 से इस क्षेत्र तथा इसके आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा जमा रखा है। अजरबैजान लगातार आरोप लगाता है कि अर्मेनिया ने नगोर्नो-काराबाख में हथियारों तथा गोला बारुद पहुंचाने के लिए लाचिन गलियारे का इस्तेमाल किया है।

अमेरिका में राजनीतिक शरण के लिए जल्द ही आवेदन करेंगे इमरान !

-पीपीपी के पदाधिकारी कुंडी ने संवाददाताओं से किया खुलासा

इस्लामाबाद (एजेंसी)। (ईएमएस)। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा राज्यमंत्री फैसल करीम कुंडी ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान जल्द ही संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण मांगेंगे। कुंडी ने संवाददाताओं से कहा कि मैं आप लोगों को कुछ खबरें देने जा रहा हूं, जो मुझे अपने सूत्रों से मिली हैं। इमरान खान जल्द ही अमेरिका में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन करेंगे।

9 मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रावलपिंडी में जनरल मुख्यालय सहित सैन्य प्रतिष्ठानों को जला दिया था और तोड़-फोड़ की थी। इस दिन को सेना ने ब्लैक डे कहा था। हिंसक विरोध के सिलसिले में पार्टी के कई नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं को गोलबंद किया गया है और सेना ने इस बात पर जोर दिया है कि सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों में शामिल लोगों पर पाकिस्तानी सेना अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाए।

खान के करीबी सहयोगी असद उमर ने मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए महासचिव और कोर कमेटी के सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया के अनुसार 9 मई की बर्बरता के बाद शिरीन मजारी, आमिर महमूद कियानी, मलिक अमीन असलम, महमूद मौलवी, आफताब सिद्दीकी और फैयाजुल हसन चौहान सहित कई पार्टी नेताओं और सांसदों ने राज्य के प्रतिष्ठानों पर हमलों की सार्वजनिक रूप से निंदा की और पूर्व सत्ताधारी दल को छोड़ने की घोषणा की।

आज से आम लोग कर सकेंगे भारत के कोहिनूर का दीदार

-टॉवर ऑफ लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य के 'विजय प्रतीक' के तौर पर किया जाएगा प्रदर्शित

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज में यह हीरा जड़ा हुआ है, जिसे पहनने से नयी महारानी कैमिला ने इनकार कर दिया था। अब यह ताज 'टावर ऑफ लंदन' में रखा हुआ है।

लंदन (एजेंसी)। भारत पर सौ साल के शासन के दौरान अंग्रेजों ने यहां से बहुत कुछ लूट कर अपनी तिजोरी में भरा। वो हीरा जो भारत से सात समुंदर पार चला गया। चर्चा तो हमेशा होती रही कि कोहिनूर को भारत लाया जाएगा। लेकिन तमाम चर्चाओं के बीच विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को टॉवर ऑफ लंदन में विजय के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। मशहूर कोहिनूर हीरा शुक्रवार यानी 26 मई को ब्रिटेन के टॉवर ऑफ लंदन में शुरू हुई प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। कोहिनूर को विजय के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाएगा। मैनेजर सोफी लेमग्नेन ने इसकी जानकारी दी है। कोहिनूर पर्यटकों के आकर्षण में नई ज्वेल हाउस प्रदर्शनी का हिस्सा है और इसके साथ एक वीडियो भी है जो दुनिया भर में हीरे की यात्रा को दर्शाता है।

सोफी लेमग्नेन ने कहा कि कोहिनूर एक बेशकीमती हीरा है, जिसका लंबा इतिहास रहा है। यह कई हस्तियों के हाथों से गुजरा है। दिवंगत

कोहिनूर की कहानी

भारत से ब्रिटेन पहुंचे कोहिनूर 105.6 कैरेट का है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है। इसका इतिहास पांच हजार साल से भी पुराना है। हीरे का वर्तमान नाम फारसी में है जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। जानकारों की मानें तो पांच हजार साल पहले इस हीरे की खोज आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खदानों में खुदाई के दौरान हुई थी। इसके बाद 1304 में ये मालवा पहुंचा। यहां से 1306 में ओरुगल्लु, 1323 में दिल्ली, 1339 में समरकंद उज्बेकिस्तान, 1526 में वापस दिल्ली, 1739 में पार्शि (मौजूदा समय में ईरान), 1747 में काबुल अफगानिस्तान, 1800 में पंजाब, 1849 में लाहौर, 1854 में ये ब्रिटेन चला गया।

हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं करते, इमरान खान की पार्टी में मची भगदड़, अब पंजाब के पूर्व शिक्षा ने छोड़ी पीटीआई

लाहौर (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक ए इंसाफ के मुखिया इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रही कार्रवाई के बाद अब नेताओं के पार्टी को अलविदा कहने का सिलसिला भी चल पड़ा है। पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री मुराद रास ने घोषणा की है कि वो पीटीआई और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से अलग हो रहे हैं। लाहौर में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हम 9 मई की आंदोलन आधारित राजनीति से सहमत नहीं हैं। रास ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी ऐसा दिन देखने की उम्मीद नहीं की थी जब वो इमरान से अलग हो जाएंगे।

लाहौर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते रास ने कहा कि 9 मई को जो हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने पीर अहमद खग्गा, राजा यावर सहित अन्य नेताओं के साथ कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम पार्टी से अलग हो जाएंगे। हम पीटीआई की हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं।

चुनाव ही देश के मुद्दों का समाधान है

पूर्व सीनेटर बाबर अवान ने कहा है कि इस समय देश में सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान चुनाव है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सभी मुद्दों का संवैधानिक समाधान पारदर्शी चुनाव है, जिसमें देश अपना भविष्य खुद तय करता है। पीटीआई नेता ने कहा कि दुनिया भर के सभी संवैधानिक देशों में ऐसा ही होता है, लेकिन पीडीएम (पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट) इसे रॉकेट साइंस के रूप में पेश कर रहा है।

अमेरिका के दुश्मन ईरान ने खतरनाक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाने वाला ईरान अब खतरनाक क्रूज मिसाइल बनाने में कामयाब हो गया है। करीब 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल ने अमेरिका, इजरायल और दूसरे कई देशों की नींद हराम कर दी है। यह बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी टॉमहॉक से भी ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। इसका सबसे ज्यादा खतरा इजरायल को बताया जा रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने 2,000 किमी (1,243 मील) की रेंज और 1,500 किलोग्राम (3,300 पाउंड) वारहेड के साथ खैबर नाम से अपनी खोर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल के चौथे संस्करण का अनावरण किया है। ईरान ने अमेरिका के विरोध और यूरोपीय देशों द्वारा चिंता व्यक्त करने के बावजूद अपने मिसाइल कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का विस्तार किया है। तेहरान का कहना है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से रक्षात्मक है और प्रतिरोध के लिए है।

ईरान की नवीनतम बैलिस्टिक मिसाइल और रक्षा मंत्रालय के एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गनाइजेशन के नवीनतम उत्पाद का गुरुवार को रक्षा मंत्री द्वारा आयोजित एक समारोह में अनावरण किया गया। बताया जाता है कि इस मिसाइल को फारस की खाड़ी में गश्त लगाने वाले युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर तैनात किया गया है। ईरानी नौसेना का कहना है कि फारस की खाड़ी में दुश्मन के जहाजों की आवाजाही पर आईआरजीसी नौसेना लगातार नजर बनाए हुए है। इस मिसाइल को अमेरिका के अलावा इजरायल के लिए बड़ा खतरा बताया जा रहा है।

रूस ने बेलारूस में रणनीतिक परमाणु हथियार की तैनाती के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किए

कीव (एजेंसी)। रूस और बेलारूस ने बृहस्पतिवार को बेलारूसी क्षेत्र पर रूसी परमाणु हथियारों को तैनात करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि हथियारों का नियंत्रण क्रेमलिन के पास रहेगा। इस कदम ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको द्वारा पहले की गई सहमति को औपचारिक रूप दिया। पुतिन ने इस साल के शुरू में घोषणा की थी कि उनके देश ने बेलारूस में सामरिक, तुलनात्मक रूप से कम दूरी और कम प्रभाव वाले परमाणु हथियारों को तैनात करने की योजना बनाई है।

इस कदम को व्यापक रूप से पश्चिम के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा गया जिसने यूक्रेन के लिए अपना सैन्य समर्थन बढ़ाया है। हथियारों को कब तैनात किया जाएगा इसकी घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन पुतिन ने कहा है कि बेलारूस में उनके लिए भंडारण सुविधाओं का निर्माण एक जुलाई तक पूरा हो जाएगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि बेलारूस में कितने परमाणु हथियार रखे जाएंगे। अमेरिकी सरकार का मानना है कि रूस के पास लगभग 2,000 रणनीतिक परमाणु हथियार हैं, जिनमें बम शामिल हैं।

इन्हें विमान द्वारा ले जाया जा सकता है और कम दूरी की मिसाइलों और तोपखानों द्वारा भी इन्हें दागा जा सकता है। रणनीतिक परमाणु हथियारों का उद्देश्य युद्ध के मैदान में दुश्मन सैनिकों और हथियारों को नष्ट करना है। करार पर हस्ताक्षर तब हुए जब रूस यूक्रेन के बहुप्रतीक्षित जवाबी हमले के लिए तैयार हो गया। रूसी और बेलारूसी दोनों अधिकारियों ने पश्चिम से शत्रुता से प्रेरित यह कदम उठाया।

बेलारूस के रक्षा मंत्री विक्टर खेनिन ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु के साथ बैठक के दौरान मिन्स्क में कहा, 'गैर-रणनीतिक परमाणु हथियारों की तैनाती हमारे लिए अमित्र देशों की आक्रामक नीति का प्रभावी जवाब है।' शोइगु ने कहा, 'रूस और बेलारूस की पश्चिमी सीमाओं पर जंग के जोखिम में तीव्र वृद्धि के संदर्भ में सैन्य-परमाणु क्षेत्र में जवाबी उपाय करने का निर्णय लिया गया था।

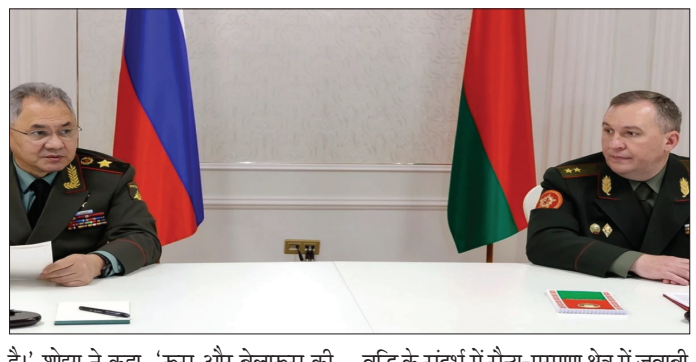

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

4 जून तक केरल पहुंचेगा मानसून, इस बार रहेगा सामान्य

नई दिल्ली । देश में इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों को अगले सप्ताहांत से राहत मिलने की उम?मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि 4 जून को मॉनसून केरल में पहुंचेगा। साथ ही उनकी ओर से कहा गया कि मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल है। अगले 2-3 दिनों में उत्तर भारत में अच्छी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कहा कि मार्च-मई में प्री-मॉनसून की अच्छी बारिश हुई है। 1 मार्च से 25 मई के दौरान 12 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है। प्री-मॉनसून सीजन में कम हीट वेव देखी गई। मौसम विज्ञानियों ने कहा कि एक बार जब मॉनसून मजबूत हो जाएगा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वह 4 जून के आसपास केरल में पहुंच जाएगा। 1 जून से पहले, हम मॉनसून के आने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। इस साल मॉनसून के सामान्य रहने की सबसे अधिक संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि अगले एक हफ्ते तक अरब सागर में चक्रवात की संभावना नहीं है। अगर बारिश हर जगह लगभग एक जैसी हुई, तब सभी जगह के लिए यह एक आदर्श स्थिति होगी। अगर हर जगह एक जैसी बारिश होगी तब कृषि पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तर पश्चिम भारत में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय से गांधी परिवार को लगा झटका

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की याचिकाएं खारिज कर दीं, जिसमें उन्होंने हथियार सौदागर संजय भंडारी से जुड़े मामले में आयकर विभाग के मूल्यांकन को सामान्य मूल्यांकन की जगह 'सेंट्रल सर्किल' में स्थानांतरित करने के विभाग के फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, यंग इंडियन और आम आदमी पार्टी की वे अलग-अलग याचिकाएं भी खारिज कर दीं, जिसमें समान कानूनी मुद्दे उठाए गए थे। गांधी परिवार ने आयकर प्रधान आयुक्त द्वारा आकलन वर्ष 2018-19 के लिए अपने मामलों को 'सेंट्रल सर्किल' में स्थानांतरित करने के संबंध में जारी आदेश को चुनौती दी थी। 'सेंट्रल सर्किल' को कर चोरी की जांच और इसकी रोकथाम का काम सौंपा गया है। वह तलाशी के दौरान जांच शाखा द्वारा एकत्र किए गए सबूतों को अपने कब्जे में ले लेता है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने फैसला सुनाकर कहा, याचिकाकर्ताओं के मूल्यांकन को कानून के अनुसार सेंट्रल सर्किल में स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्तमान रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। दरअसल गांधी परिवार ने अपने मामले 'सेंट्रल सर्किल' को स्थानांतरित करने का विरोध करते हुए दलील दी थी कि उनका भंडारी समूह के मामलों से कोई लेना-देना नहीं है। धन शोधन के आरोपों में भारत में वांछित भंडारी के प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाद्रा के साथ, लंदन स्थित फ्लैट को लेकर कथित संबंध बताए जाते हैं। रॉबर्ट वाद्रा ने भंडारी के साथ कोई भी कारोबारी संपर्क होने से इंकार किया है।

मुस्लिम महिला से दोस्ती करना पड़ा महंगा, बजरंग दल कार्यकर्ता की हो गई पिटाई

चिक्कमंगलुरु (कर्नाटक)। कर्नाटक के चिक्कमंगलुरु जिले में 30 लोगों के समूह ने शुक्रवार को एक मुस्लिम युवती से दोस्ती करने पर बजरंग दल के एक कार्यकर्ता पर हमला कर दिया। पुलिस ने मीडिया को शुक्रवार को यह जानकारी दी। पीड़ित की पहचान अजीत के रूप में हुई है। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना मुदिगेरे तालुक के बनकल पुलिस थाने की सीमा में हुई। समूह ने अजीत पर उस समय हमला किया, जब वह युवती के साथ जा रहा था। पुलिस ने कहा कि उसे सड़क पर घसीटा गया और हमला किया गया। महिला ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। अजीत का मुदिगेरे के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री सिध्दारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की कड़ी चेतावनी के बाद राज्य में यह दूसरी नैतिक पुलिसिंग की घटना है। 24 मई को चिक्काबल्लापुर जिले से नैतिक पुलिसिंग की एक और घटना सामने आई और पुलिस ने मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि चिक्कमगलुरु सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिला है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जिले की सभी 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। चिक्कमंगलुरु के रहने वाले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था।

एआईएमआईएम व बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट

-मेयर व पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम को लेकर बवाल

मेरठ । उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला स्थित चौधरी चरण सिंह विश्विद्यालय के नेताजी सुभाषचंद बोस प्रेक्षागृह में शुक्रवार को मेयर सहित निगम और नगर पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह वंदे मातरम से शुरू हुआ, जिसका एआईएमआईएम के सदस्यों ने विरोध किया। बीजेपी के लोगों ने उन्हें खड़े होने को कहा। बस यहीं से ही विवाद शुरू हो गया और मारपीट तक जा पहुंचा। शुक्रवार को शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। मंच पर मेरठ कमिश्नर जे सेल्वा कुमारी मेयर और पार्षदों को शपथ दिलाने पहुंची थीं। मंच पर बैठीं। जिलाधिकारी और एसपी ट्रैफिक सीओ भरी फोर्स के साथ व्यवस्था संभाले हुए थे। एआईएमआईएम के सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रगान गा लेंगे, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल देंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम बीजेपी का नहीं है, ये मेयर और पार्षदों का है और जितनी भी बीजेपी की गुंडागर्दी हुई है, वो सब जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुई है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे ये लोग क्या करेंगे।

तूफानी बारिश में राजस्थान में 14 लोगों की हुई मौत

-कई घायल, कई सारे जानवरों की गई जान

जयपुर। राजस्थान में प्रदेशभर में गुरुवार रात आए तेज अंधड़ ने जमकर कहर बरपाया। तूफानी बारिश के चलते प्रदेशभर में 14 लोगों की मौत हुई है। वहीं, एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। तूफानी बारिश से राजधानी जयपुर, दौसा, टोंक, भरतपुर, अलवर, बाड़मेर, बारां, सवाई माधोपुर, सीकर, अजमेर, करौली, धौलपुर सहित कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। बारिश ने सबसे ज्यादा टोंक जिले में कहर बरपाया। तूफानी बारिश के बीच जगह-जगह लगे टिन शेड के अलावा होर्डिंग्स और बैनर उड़ गए। वहीं, अधिकतर जगह हजारों पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए। हालांकि, मौसम के बदले मिजाज से आज भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जानकारी के मुताबिक तूफानी बारिश के चलते सबसे ज्यादा 12 लोगों की मौत टोंक जिले में हुई और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। टोंक शहर में टीनशेड का मकान धराशायी होने से दादा सहित पोते-पोती की मौत हो गई। वहीं, कहीं दीवार गिरने और कहीं टीनशेड उड़ने के कारण निवाई में दो बच्चों सहित 3 की मौत हो गई। मालपुरा में 2, टोकरावास, आवां, टोडारायसिंह और उनियारा में 1-1 की जान गई है। इधर, श्रीगंगानगर जिले में घर की दीवार गिरने से एक किशोरी की मौत हो गई। वहीं, अजमेर के देव खेड़ी गांव में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ के नीचे बैठे एक किसान की मौत हो गई। जयपुर के दूदू में दीवार गिरने और टीनशेड उड़ने से 15 बकरियों की मौत हो गई। इसके अलावा कई जिलों में तेज अंधड़ के चलते सैकड़ों पक्षियों की जान चली गई। राजधानी सहित प्रदेशभर में देर रात की बरसात-तूफान से पावर सप्लाई सिस्टम को बड़ा नुकसान हुआ है। जयपुर जिले के कई इलाकों में विद्युत पोल और लाइन टूटकल गिरने की सूचना है। कहीं पर फॉल्ट तब कहीं पर पावर सिस्टम की दिक्कत से बिजली सप्लाई बाधित है। प्रभावित उपभोक्ता जयपुर डिस्कॉम के कॉल सेंटर पर लगातार कॉल कर रहे हैं. लेकिन एक साथ आई शिकायतों के चलते अधिकांश उपभोक्ताओं को निराशा मिली है। हालांकि, अधिकांश स्थानों पर अब बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से संचालिय हो गई है। तूफान ने प्रदेशभर के साथ टोंक में कोहराम मचा दिया। टोंक जिले में 3 बालिकाओं सहित 8 लोगों की मौत होने की जानकारी आ रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया है। वहीं जिलेभर में कई स्थानों पर जानवरों की मौत होने की भी जानकारियां सामने आ रही है।

कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सोनिया और राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने की मुलाकात

नई दिल्ली (एजेंसी)। कर्नाटक राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के एक दिन बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व सांसद राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। दिल्ली पहुंचे सीएम सिद्दारमैया ने बेंगलुरू में बीते शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार सोनिया गांधी से मुलाकात की।

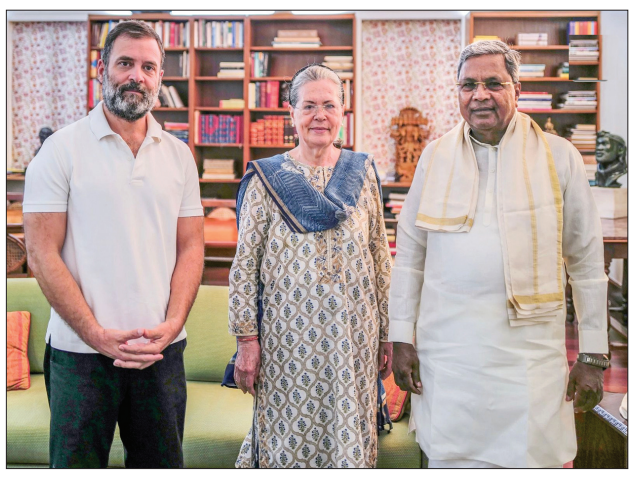

तीनों नेताओं के बीच बैठक 30 मिनट से अधिक समय तक चली, इस दौरान उन्होंने राज्य के लोगों से पार्टी द्वारा किए गए वादों को पूरा करने और शासन पर ध्यान केंद्रित करने पर भी चर्चा की। यह भी पता चला है कि नेताओं ने राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। इसके पहले सिद्दारमैया ने डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और पार्टी महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। सुरजेवाला और वेणुगोपाल के साथ सिद्दारमैया और शिवकुमार की बैठक के दौरान कम से कम 20 से 24 नामों पर चर्चा हुई।

सूत्र ने कहा कि 20 से 24 और मंत्री शनिवार को पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे के करीब शपथ ले सकते हैं। हालांकि, वरिष्ठ पार्टी के नेताओं ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा। शनिवार को सिद्दारमैया के मुख्यमंत्री व डीके शिवकुमार के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के अलावा आठ और मंत्री जी. परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, सतीश जारकीहोली, प्रियंका खड़गे, रामालिमगा रेड्डी और बी.जेड. जमीर अहमद खान ने भी शपथ ली थी।

हालांकि, उसमें से किसी को भी अभी तक कोई पोर्टफोलियो आवंटित नहीं किया गया है। सूत्र ने कहा कि कांग्रेस को कैबिनेट आवंटन में संतुलन बनाना होगा, क्योंकि उसे विभिन्न समुदायों की मांगों को संतुलित करने की जरूरत है। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिंगायत समुदाय, को कैबिनेट में अधिक स्थान मिलने की उम्मीद है।

ड्रैगन की हिमाकत, उत्तराखंड के समीप बार्डर के करीबी गांव बसा रहा

नई दिल्ली । चीन एलएसी पर भारत को घेरने के लिए लगातार अपने प्रयास कर रहा हैं। रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल और लद्दाख में पीएलए द्वारा गतिरोध बढाने के बाद अब चीन उत्तराखंड की ओर से भी भारत को घेरने का प्रयास कर रहा हैं। चीन पहले से ही भारत के साथ लंबे समय से सीमा गतिरोध में उलझा हुआ है। अब चीन ने नई चाल चली है और उत्तराखंड से सटे बॉर्डर के पास सीमा रक्षा गांवों का निर्माण कर रहा है। 250 घरों वाले ये सीमावर्ती गांव वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से 11 किलोमीटर दूर बनाए जा रहे हैं। चीन उत्तराखंड से सटे एलएसी से करीब 35 किलोमीटर दूर करीब 55-56 घरों के निर्माण में भी शामिल रहा है, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की निगरानी में रहते हैं। उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अधिकांश सीमावर्ती गांवों में आजीविका के अवसरों की कमी के कारण बाहरी प्रवास देखा जाता है। ये गाँव सभी सुविधाओं से सुसज्जित बड़े परिसर हैं। भारतीय सेना ने पहले कहा था कि वह एलएसी के साथ स्थिति की निगरानी कर रही थी, जो भारत और चीन के बीच की सीमा है। बीआरओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत-चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे की अंतिम सीमा चौकी तक जाने के रास्ते को और सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड में घाटियाबागर-लिपुलेख मार्ग पर बूंदी और गरबियांग के बीच छह किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा।

विपक्षी दलों को संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह में अंतर समझना चाहिए : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली (एजेंसी)। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राजनीतिक बवाल जारी है। 20 विपक्षी दलों ने इसके बहिष्कार की घोषणा की है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि, विपक्षी दलों के आरोपों पर केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया है। राजनाथ ने कहा कि हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह में अंतर समझना चाहिए। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों से बहिष्कार के निर्णय पर फिर से विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 28 मई को प्रधानमंत्री नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है।

रक्षामंत्री सिंह ने कहा कि संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक क्षण है, जो 21वीं सदी में फिर नहीं आएगा। हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह में अंतर समझना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि जिन राजनीतिक दलों ने बहिष्कार का निर्णय लिया है, वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर फिर विचार करें। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहूंगा। संवैधानिक मुखिया के अधिकार सिर्फ इसकारण नहीं छीने जा सकते कि वह एक आदिवासी महिला है। वह हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए।

विपक्षी दलों द्वारा नए संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर जेडीएस नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि इस तरह का उद्घाटन समारोह छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी किया गया। कर्नाटक में जब विकास सौधा का उद्घाटन हुआ था तब उन्होंने रमा देवी को उस समय आमंत्रित नहीं किया था जबकि वह उस समय कर्नाटक की राज्यपाल थी। तब अब ये राजनीति क्यों...मैं उनसे पूछना चाहता हूं। अब वे राष्ट्रपति के प्रति बहुत स्नेह और सम्मान दिखा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि राष्ट्रपति चुनाव के समय उन्होंने उनके खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़ा किया? अब वे कह रहे हैं कि भाजपा आदिवासियों का अपमान कर रही है। यह सब केवल लोगों का ध्यान हटाने और समाज के एक वर्ग से वोट हासिल करने के लिए है।

सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी को झटका

-कोलकता हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को फिलहाल राहत नहीं मिलती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोलकता हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाने से मना किया , जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को बंगाल स्कूल नौकरियों घोटाले के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने के लिए कहा गया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस निर्देश पर भी रोक लगा दी, जिसमें रिकॉल अर्जी दाखिल करने पर उस पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। कोर्ट ने मामले को 10 जुलाई को सूचीबद्ध किया है।

घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए सीबीआई द्वारा बुलाने के कुछ दिनों बाद अभिषेक ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की धमकियां उन्हें सार्वजनिक सेवा से नहीं रोक सकतीं। सीबीआई और ईडी पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं में अभिषेक की कथित भूमिका की जांच कर रही हैं। भर्ती घोटाला 2016 में बंगाल की शिक्षा प्रणाली में हजारों शिक्षकों की भर्ती से संबंधित है। भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियों का आरोप लगाकर उच्च न्यायालय में याचिकाओं की एक श्रृंखला दायर की गई थी, और कई मामले अदालत द्वारा उठाए गए थे।

डायमंड हार्बर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसी को चुनौती दी कि अगर उसके पास उनके खिलाफ भ्रष्टाचार अथवा कदाचार के सबूत हैं, तब वह उन्हें गिरफ्तार करे। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता बनर्जी ने अपना जनसंपर्क अभियान 'तृणमूले नवज्वार' सोमवार को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले से फिर से शुरू किया। बनर्जी ने अपना यह जनसम्पर्क अभियान पिछले सप्ताह शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा तलब किए जाने के बाद दो दिनों के लिए स्थगित कर दिया था।

समझौते के आधार पर नहीं की जा सकती एफआईआर रद्दः कोर्ट

-मजदूर की मौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय

मुंबई (एजेंसी)। व्यावसायिक नगरी मुंबई की निर्माणधीन गगनचुंबी इमारतों में सुरक्षा उपायों के अभाव में मजदूरों की मौत हो रही है। हालांकि, ऐसे उपाय करना डेवलपर, ठेकेदार व सुपरवाइजर की कानूनी जिम्मेदारी है, ताकि इमारत से गिरने पर मजदूरों को जानलेवा चोट से बचाया जा सके। कोर्ट ने यह बात मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व स्थित आदर्श नगर इलाके में निर्माणाधीन इमारत की 13वीं मंजिल से गिरने के चलते एक मजदूर की मौत से जुड़े मामले में आरोपी सुपरवाइजर की याचिका को खारिज करते हुए कही। कोर्ट ने कहा कि केवल समझौते के आधार पर इस तरह के केस को लेकर दर्ज की जाने वाली एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है।

फरवरी 2018 में मजदूर भुवनेश्वर प्रसाद की भवन से गिरने के कारण मौत हो गई थी। ओशिवरा पुलिस ने इस केस में इमारत का काम देख रहे सुपरवाइजर जिग्नेश पटेल को आरोपी बनाया है। पटेल ने खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिका में आरोपी ने दावा किया था कि मजदूर के परिजन को बीमा की राशि का भुगतान कर दिया गया है। परिजन को एफआईआर रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस हादसे में उसकी कोई भूमिका नहीं है। मजदूर के परिजनों को केस रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है। जस्टिस एसबी शुक्रे एवं जस्टिस एमएम साठे की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि किसी आपराधिक मामले को रद्द करते समय उसके स्वरूप, उसकी गंभीरता को देखा जाता है। निजी व सिविल स्वरूप के अपराध को छोड़कर अन्य मामलों से जुड़ी एफआईआर सिर्फ इसलिए रद्द नहीं हो सकती है, क्योंकि पक्षकारो ने अदालत के बाहर समझौता कर लिया है। मौजूदा मामले में आरोपी सुपरवाइजर पर तो इमारत में काम करने वाले मजदूरों के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय करने में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप है।

केंद्रीय मंत्री शाह का हमला, कांग्रेस को भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों

-कांग्रेस नेता जयराम रमेश सेंगोल का दावा फर्जी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री शाह ने लिखा है, कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है? भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ द्वारा पंडित नेहरू को एक पवित्र सेंगोल (राजदंड) दिया गया था, लेकिन इस 'वॉकिंग स्टिक' के रूप में एक संग्रहालय में भेज दिया गया था। अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ, थिरुवदुथुराई अधीनम ने स्वयं भारत की स्वतंत्रता के समय सेंगोल के महत्व के बारे में बात की थी। कांग्रेस अधीनम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया था कि लॉर्ड माउंटबेटन, सी. राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा 'सेंगोल' को अंग्रेजों द्वारा भारत में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में वर्णित करने का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, इस आशय के सभी दावे पूरी तरह से

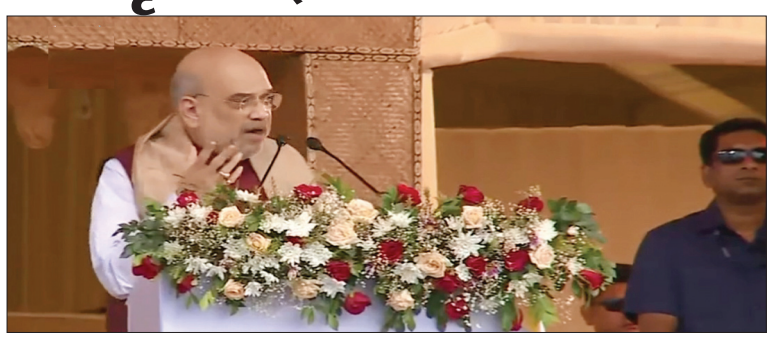

बोगस और कुछ लोगों के दिमाग में निर्मित हैं। कांग्रेस नेता रमेश ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और उनकी ढपली बजाने वाले तमिलनाडु में अपने राजनीतिक फायदे के लिए औपचारिक राजदंड का इस्तेमाल कर रहे हैं।

इसके पहले भारत के पहले भारतीय गवर्नर-जनरल सी. राजगोपालाचारी (जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है) के परपौते सीआर केसवन ने नए संसद भवन में ऐतिहासिक 'सेंगोल' स्थापित करने के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की थी। उन्होंने कहा, भारत की सभ्यतागत विरासत और परंपराओं की गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति ही यह सुनिश्चित कर सकता था कि इस तरह की महत्वपूर्ण घटना को इतिहास में उचित स्थान दिया जाए।

भाजपा नेता केसवन ने कहा, हम में से बहुत लोग पवित्र राजदंड जो कि 'सेंगोल' है, उसके साथ अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण की इस महत्वपूर्ण घटना के बारे में नहीं जानते। एक भारतीय के रूप में, मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हें भारत की सभ्यतागत विरासत और परंपराओं की बहुत गहरी समझ है। भारतीय संस्कृति और हमारे मूल्यों के प्रति गहरा सम्मान रखने वाला ही यह सुनिश्चित कर सकता था कि इस तरह की एक महत्वपूर्ण घटना को गुमनामी से वापस लाया जाए और इतिहास में उचित स्थान दिया जाए।

दबाव के आगे झुके बिना कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करें नौकरशाह : सक्सेना

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में वी. के. सक्सेना के कार्यकाल का एक साल शुक्रवार को पूरा हो गया तथा इस अवसर पर उन्होंने अपने प्रशासन में किए गए कार्यों को सूचीबद्ध किया और दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले एक दशक में भी इतना काम नहीं हुआ है। उपराज्यपाल ने प्रभावी सेवा मुहैया कराने के लिए लोक सेवकों की क्षमता निर्माण संबंधी कार्यशाला में अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) काडर के आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारियों को संबोधित करते हुए उनसे दबाव के आगे झुके बिना ईमानदारी और कड़ी मेहनत से काम करने को कहा।

उन्होंने कहा, ''दबाव के आगे झुके बिना कड़ी मेहनत एवं ईमानदारी से काम करो। कोई आपको छू नहीं सकता। आपका कोई नुकसान नहीं होगा।'' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और दानिक्स (दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप सिविल सेवा) कैडर के अधिकारियों के स्थानांतरण तथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के वास्ते शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया।

पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि मामलों को छोड़कर अन्य सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली की निर्वाचित सरकार को देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के एक सप्ताह बाद केंद्र का अध्यादेश आया। सक्सेना ने उनकी निगरानी में दिल्ली में हुए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा, ''हमने आपके सहयोग से एक साल में इतना काम किया है, जो शायद 10 साल में भी नहीं हो सकता था।'' उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में दिल्ली में 17 हजार लोगों को पक्की नौकरी दी गई। उन्होंने कहा कि अत्यधिक दूषित यमुना में एक प्रत्यक्ष बदलाव आया है और उम्मीद है कि नदी का पुराना गौरव बहाल हो जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 28 साल और उसके बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आठ साल तक नदी की सफाई की निगरानी की, लेकिन नतीजा ''सिफर'' निकला।

उन्होंने कहा कि एनजीटी के आठ जनवरी के आदेश के बाद उन्हीं अधिकारियों के कार्यों में उल्लेखनीय अंतर आया है जो पहले भी परियोजना में शामिल थे। इस आदेश के तहत यमुना की सफाई के लिए उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया था। सक्सेना ने दिल्ली जल बोर्ड के एक सहायक अभियंता का उदाहरण दिया, जो अपने भाई की मौत हो जाने के बावजूद एक दिन की छुट्टी के बाद काम पूरा करने के लिए ड्यूटी पर लौट आया था। उन्होंने कहा, ''ऐसे जुनून और समर्पण के सामने कोई भी काम मुश्किल नहीं है।'' उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली के दामन के 'कलंक' तीन 'कचरे के पहाड़ों' (लैंडफिल स्थलों) को हटाने के काम में पिछले एक साल में तेजी आई है।

सक्सेना ने दिल्ली सरकार के आईएएस अधिकारियों से कहा कि नौकरशाही मूल्यों पर आधारित एक प्रणाली है, जिसमें करुणा, कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण समाहित है। उन्होंने कहा, ''यह प्रणाली उस समय ढह जाती है, जब नौकरशाह लोगों से दूरी बनानी शुरू कर देते हैं। नौकरशाहों को लोकसेवक बनने के बजाए स्वयं को मालिक समझने की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है।'' उन्होंने कहा कि यदि नौकरशाह स्वयं बाहर जाकर जमीनी हकीकत को नहीं समझेंगे, तो अपने कक्षों में बैठकर लिए गए उनके फैसले गलत साबित होंगे। उपराज्यपाल ने कार्यशाला में मौजूद मुख्य सचिव नरेश कुमार की सराहना करते हुए उन्हें ऐसा ''कर्मयोगी'' बताया जो चौबीसों घंटे काम करने के लिए तैयार रहते हैं।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

समस्या आपकी हमें भेजे

अपने क्षेत्र में समस्याएं

हमें लिखे या बताएँ

और समस्याएं का हल

संबंधित विभाग से मिलेगा

मोबाईल:-9879141480

या फोटा,वीडियो हमें भेजे

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार

में प्रेसनोट,नोटिस,वेपार

संबंधित संपर्क करें

पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023

संपर्क नं.-9879141480

ईमेल:-krantisamay@gmail.com

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार

भारत के अन्य राज्यों में जिला ब्यूरों

और अन्य शहर,ग्राम में पत्रकारों

की नियुक्त के लिए आवेदन कर सकते है

पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023

संपर्क नं.-9879141480

ईमेल:-krantisamay@gmail.com